Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 353
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
रविवार, 28 दिसम्बर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर तीन महीने के लिए...

4 उत्तर भारत में जहरीली हवा का घेरा...

7 बीसीसीआई ने किया अंडर-19 विश्व कप टीम ...

संक्षिप्त न्यूज

तमिलनाडु में द्रविड़ मॉडल की गूंज, सीएम स्टालिन बोले- हमें वोट न देने वाले भी कर रहे काम की तारीफ

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी सरकार के कामकाज और जनकल्याणकारी योजनाओं ने राज्य में मजबूत पहचान बनाई है। उन्होंने दावा किया कि डीएमके को वोट न देने वाले लोग भी द्रविड़ मॉडल शासन की सराहना कर रहे हैं। तिरुवन्नामलाई जिले में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की विपक्षी पार्टियों पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु में उनकी सरकार हर जिले और हर परिवार के विकास के लिए काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उद्योग जैसे क्षेत्रों में राज्य ने कई चुनौतियों को पार करते हुए उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार के कामकाज की आलोचना उसके अपने समर्थक भी कर रहे हैं, जबकि तमिलनाडु सरकार को व्यापक समर्थन और सम्मान मिल रहा है।

राज्य के अधिकार और राज्यपाल का मुद्दा

स्टालिन ने आरोप लगाया कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों का कर पर अधिकार कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के बकाया फंड जारी नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल को केंद्र ने चुनी हुई सरकार को परेशान करने के लिए नियुक्त किया है। इन सभी बाधाओं के बावजूद राज्य ने आर्थिक और सामाजिक विकास में बेहतर प्रदर्शन किया है।

विपक्ष पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्हें धोखेबाज और गुलाम बताया। उनका इशारा मुख्य विपक्षी एआईएडीएमके और उसकी सहयोगी भाजपा की ओर माना जा रहा है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु की प्रगति से कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और नफरत फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है।

बीएमसी चुनाव

बीजेपी को 128 और शिवसेना 79 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, बची 20 सीटों के लिए ये है प्लान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति की बड़ी बैठक हुई. इसमें सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है. मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और महायुति के वरिष्ठ नेता शामिल हुए. महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने बैठक के बाद कहा कि मीटिंग में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संयुक्त रैली कहां आयोजित की जाएगी और चुनाव प्रचार की दिशा क्या होगी, इस पर भी चर्चा हुई.

उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है. बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी. इस तरह कुल 207 सीटों पर समझौता हो गया है. बची 20 सीटों पर वरिष्ठता और जमीनी स्तर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा कि किस दल का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा.

क्या बोले पूर्व सांसद राहुल शेवाले?

वहीं शिवसेना नेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने भी सीट बंटवारे पर सहमति की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि बीजेपी को 128 और शिवसेना को 79 सीटें देने पर सहमति बनी है. जबकि बची हुई 20 सीटों पर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श कर अंतिम फैसला लेंगे. इस सहमति के बाद बीएमसी चुनाव में महायुति की रणनीति और चुनावी दिशा लगभग स्पष्ट मानी जा रही है.

15 जनवरी को वोटिंग और काउंटिंग 16 को

बता दें कि राज्य में नगर निगम चुनावों की गहमागहमी तेज है. निगम चुनावों का कार्यक्रम घोषित हो चुका है. मतदान 15 जनवरी और मतगणना 16 जनवरी को होगी. नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू है. नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है. इसी बीच राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी आई है.

उद्धव ठाकरे और एमएनएस गठबंधन के लिए चुनौती

शिवसेना के शिंदे गुट और बीजेपी ने राज्य की कई नगर निगम सीटों पर गठबंधन कर लिया है. बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट ने कल्याण और डोंबिवली नगर निगमों के लिए भी गठबंधन किया है, जो कि उद्धव ठाकरे और एमएनएस के गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है.

असम में 10.56 लाख वोटर्स के नाम कटे! चुनाव से पहले बड़ा झटका, बदलेंगे सियासी समीकरण?

गुवाहटी। शनिवार को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का मसौदा जारी किया और बताया कि असम में विशेष मतदाता सूची संशोधन के बाद मतदाता सूची से 10.56 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। असम में विधानसभा चुनाव छह महीने से भी कम समय में होने वाले हैं। चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को जारी एकीकृत मसौदा सूची के अनुसार, राज्य में कुल 2,51,09,754 मतदाता हैं, जिनमें 93,021 संदिग्ध मतदाता शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, मृत्यु, स्थानांतरण या एकाधिक प्रविष्टियों के कारण 10,56,291 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।

असम में 'डी-वोटर्स' एक विशेष वर्ग के मतदाता हैं जिन्हें कथित तौर पर नागरिकता संबंधी उचित प्रमाण पत्रों की कमी के कारण सरकार द्वारा मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। 'डी-वोटर्स' का निर्धारण विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाता है और 'डी-वोटर' घोषित व्यक्ति को मतदाता कार्ड नहीं दिया जाता है। 'डी-वोटर्स' से संबंधित सभी विवरण, जैसे नाम, आयु और फोटो, बिना किसी बदलाव के मसौदा मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए हैं। 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर-घर जाकर किए गए विशेष पुनरीक्षण के सत्यापन के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई।

'विदेश नीति एक पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे देश की', थरूर के बयान पर सियासत; भाजपा बोली- राहुल को...

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक बयान को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने थरूर के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि शशि थरूर ने एक बार फिर हिम्मत दिखाते हुए राहुल गांधी को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे देश की होती है और थरूर ने यह बात बिल्कुल सही कही है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत के खिलाफ गलत प्रचार करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर भी देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्टी और देश के हित से ज्यादा परिवार के हित को प्राथमिकता देते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी की भाजपा से नफरत, भारत से नफरत में बदल जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में थरूर जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वहां राष्ट्रीय हित को परिवार से ऊपर रखने की सोच को बर्दाश्त नहीं किया जाता।

वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने इस पूरे मामले पर अलग रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। यह शशि थरूर की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन पार्टी की सोच जरूरी नहीं कि वही हो। हनुमंत राव ने यह भी कहा कि अगर कोई दूसरी पार्टी ऐसा बयान देती, तो शायद तुरंत कार्रवाई होती, लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र है और अलग-अलग राय रखने की आजादी है।

अतिक्रमण के खिलाफ अभियान का सीएम सिद्धारमैया ने किया बचाव, बोले- अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई जरूरी

बंगलूरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को बंगलूरू के फकीर कॉलोनी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ जरूरी कदम था। सिद्धारमैया ने यह टिप्पणी तब की, जब उनके केरल के समकक्ष पिनरई विजयन का बयान सामने आया। विजयन ने बंगलूरू में कथित बुलडोजर कार्रवाई की निंदा की थी।

विजयन ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक की राजधानी में अल्पसंख्यक आवासीय क्षेत्रों में इमारतों को ध्वस्त करना आश्चर्यनजक और दुखद घटना है। वहीं, दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सिद्धारमैया ने कहा कि 2019 से पांच एकड़ के भूखंड पर अवैध रूप से रह रहे थे, जो ठोस कचरा प्रबंधन के लिए निर्धारित था। उन्होंने कहा, वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। इसलिए अधिकारियों ने अवैध तरीके से कब्जा करने वालों को नोटिस भेजा और उन्हें खाली करने के लिए कहा। जब उन्होंने खाली नहीं किया, तो उन्हें बेदखल किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बृहत बंगलूरू प्राधिकरण (जीबीए) के मुख्य आयुक्त और शहरी विकास विभाग के सचिव से आग्रह किया है कि बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्योंकि इनमें अधिकांश प्रवासी हैं।

उन्होंने कहा, वे अन्य जगहों से यहां आए हैं, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से हमें उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी और उन्हें रहने की जगह प्रदान करनी होगी।

कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने विजयन को सलाह दी कि पहले अपने राज्य का पर फोकस करें।

रेड्डी ने कहा, वह अपने राज्य का ध्यान रखें, हम अपने राज्य का देखेंगे। हालांकि, मुझे नहीं पता कि उन घरों को क्यों बेदखल किया गया क्योंकि मैं शहर में नहीं था। मुझे विवरण मिलने के बाद ही प्रतिक्रिया दूंगा।

विजयन ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक की राजधानी में अल्पसंख्यक आवासीय क्षेत्रों में इमारतों को ध्वस्त करना आश्चर्यनजक और दुखद घटना है। वहीं, दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सिद्धारमैया ने कहा कि 2019 से पांच एकड़ के भूखंड पर अवैध रूप से रह रहे थे, जो ठोस कचरा प्रबंधन के लिए निर्धारित था। उन्होंने कहा, वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। इसलिए अधिकारियों ने अवैध तरीके से कब्जा करने वालों को नोटिस भेजा और उन्हें खाली करने के लिए कहा। जब उन्होंने खाली नहीं किया, तो उन्हें बेदखल किया गया।

गरीबों के 'काम का अधिकार' छीना! सीडब्ल्यूसी की बैठक में खरगे बोले- एमजीएनआरईजीए पर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को निरस्त किए जाने के खिलाफ एक सशक्त राष्ट्रीय अभियान चलाने का आह्वान किया है। यह अधिनियम यूपीए सरकार का एक महत्वपूर्ण कानून था जो ग्रामीण रोजगार प्रदान करता था। खरगे ने इस स्थिति की तुलना सरकार की पिछली कार्रवाइयों से की, जैसे कि जनता के आक्रोश के बाद कृषि कानून निरस्त किए गए।

खरगे ने कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक को संबोधित करते हुए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा की और कहा कि इससे पूरा भारत चिंतित है। खरगे ने कांग्रेस नेताओं से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने का आह्वान किया और यह भी कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की एक सोची समझी साजिश है तथा ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा कि कांग्रेस के मतदाताओं के नाम न काटे जाएं

खरगे ने बैठक में कहा कि हम आज ऐसे मौके पर विचार और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जब देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर चारों तरफ गंभीर संकट छाया है।'

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि हाल में संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर करोड़ों गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया है। गरीबों के पेट पर लात मारने के साथ उनकी पीठ में मोदी सरकार ने छुरा घोंपा है। मोदी सरकार ने काम के अधिकार पर सुनियोजित और क्रूर हमला किया है। खरगे ने कहा कि मोदी सरकार को गरीबों की चिंता नहीं, बल्कि चंद बड़े पूंजीपतियों के मुनाफ़े की ही चिंता है। उनका कहना था कि मनरेगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार का ऐसा दूरदर्शी कदम था, जिसे पूरे विश्व ने सराहा।

वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस योजना ने ग्रामीण भारत का चेहरा बदला। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बना। इससे पलायन रुका, गांवों को अकाल, भूख, और शोषण से मुक्ति मिली। इस योजना ने दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और भूमिहीन मज़दूरों को भरोसा दिया कि गरीबी से जंग में सरकार उनके साथ खड़ी है।'' खरगे ने दावा किया कि मोदी सरकार ने बिना किसी अध्ययन या मूल्यांकन के, राज्यों से या राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा के बिना इसे खत्म करके नया कानून थोप दिया। उन्होंने कहा कि यह सारा काम तीन काले कृषि कानूनों जैसा किया गया।

कर्नाटक में सीएम पद पर खींचतान!

सिद्धारमैया, डीके के बाद परमेश्वर ने भी ठोका दावा, समर्थकों ने भी भरी हुंकार

बैंगलुरू। कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता जी परमेश्वर के समर्थक शनिवार को दिल्ली में इंदिरा भवन के पास जमा हुए और मांग की कि उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। परमेश्वर के समर्थक पार्टी के मजबूत समर्थन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समर्थन को एकजुट करने के उनके प्रयासों के कारण उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में एक दलित नेता को नियुक्त करने का आग्रह किया, जिसमें समुदाय के भीतर परमेश्वर के मजबूत समर्थन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समर्थन को एकजुट करने के उनके प्रयासों को रेखांकित किया गया।

एक समर्थक ने कहा कि हम कर्नाटक से दिल्ली आए हैं कर्नाटक के लिए एक दलित मुख्यमंत्री की मांग करने के लिए। अगर सिद्धारमैया को कभी मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है, तो उनकी जगह जी परमेश्वर को नियुक्त किया जाना चाहिए। एक अन्य समर्थक ने कहा कि हम जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं कर्नाटक के तुमकुर से हूं। अगर कभी मुख्यमंत्री बदला जाता है, तो हम चाहते हैं कि

जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाया जाए... हमें एक दलित मुख्यमंत्री चाहिए।

हालांकि, मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का रास्ता जटिल है, क्योंकि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस पद के लिए दावेदार हैं और कथित तौर पर पार्टी के उच्च कमान को प्रभावित कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के भीतर की खींचतान को उजागर करते हैं, जहां कई नेता सत्ता हथियाने की होड़ में लगे हैं। कर्नाटक मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा विवाद कांग्रेस पार्टी के भीतर एक निरंतर सत्ता संघर्ष है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार ने अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिया, जिससे नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगने लगीं। प्रमुख खिलाड़ियों में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और गृह मंत्री जी परमेश्वर शामिल हैं, जो एक प्रमुख दलित नेता भी हैं।

परमेश्वर ने शीर्ष पद के लिए अपनी दावेदारी का संकेत देते हुए पार्टी की सफलता में अपने योगदान पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, 'मैं उस समय स्वाभाविक रूप से इस दौड़ में था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में यह परंपरा है कि पीसीसी अध्यक्ष को अक्सर मौका दिया जाता है।

केरल के सीएम विजयन को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का जवाब- हमारे राज्य के मामले में दखल न दें

बंगलूरू। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को केरल के मुख्यमंत्री को उत्तरी बंगलूरू में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने शुक्रवार को कर्नाटक की राजधानी में मुस्लिम आवासीय क्षेत्रों को कथित तौर पर ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए इस कार्रवाई को चौंकाने वाला और पीड़ादायक बताया। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में वर्षों से रह रहे मुस्लिम परिवारों के घर गिराए जाना दर्दनाक और चौंकाने वाला है।

'बिना तथ्य जाने हमारे राज्य के मामलों में दखल न दें'

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डी के शिवकुमार ने कहा, 'यह पूरी तरह एक राजनीतिक बयान है। बिना तथ्य जाने पिनरई विजयन को हमारे राज्य के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। यह चुनाव के समय किया गया राजनीतिक हथकंडा है।' शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि जिस जमीन पर झुग्गियां बनी थीं, वह ठोस कचरा प्रबंधन के लिए नौ साल पहले अधिसूचित की गई थी। उन्होंने कहा कि यह जगह एक पुरानी खदान और कचरा डंपिंग साइट है, जो बेहद खतरनाक और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा 'कुछ लोगों ने रातों-रात अवैध रूप से कब्जा कर लिया। यह जमीन हड़पने का मामला है। इसमें किसी समुदाय को निशाना बनाने की बात बिल्कुल गलत है।'

'मध्यस्थता अपनाने के लिए सोच बदलना जरूरी', जस्टिस ने बताया कैसे कम होगा अदालतों का बोझ

नई दिल्ली। देश में विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता को व्यापक रूप से अपनाने के लिए लोगों की सोच में बदलाव और जमीनी स्तर पर भरोसा पैदा करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ए अमानुल्लाह ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक आम लोगों में यह विश्वास नहीं बनेगा कि मध्यस्थता उनके हित में है, तब तक यह व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाएगी।

राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि अक्सर लोग मध्यस्थता को पंचाट से जोड़कर देखते हैं, जबकि दोनों प्रक्रियाएं मूल रूप से अलग हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक मध्यस्थ का नजरिया पंच की तरह नहीं हो सकता। मध्यस्थता का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच संवाद के जरिए समाधान निकालना होता है, न कि किसी एक को विजेता और दूसरे को पराजित घोषित करना।

मुकदमेबाजी से मुक्ति का रास्ता

जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि जब किसी विवाद का समाधान मध्यस्थता से होता है, तो इससे मध्यस्थ को भी गहरी संतुष्टि मिलती है। आम लोग भी चाहते हैं कि उनके झगड़े अदालतों में वर्षों तक न चलें और पीढ़ियों तक न खिंचें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति लंबी कानूनी लड़ाई नहीं चाहता, बल्कि सम्मानजनक और शांतिपूर्ण समाधान चाहता है।

न्याय प्रणाली से अलग, लेकिन समानांतर व्यवस्था

उन्होंने यह भी कहा कि मध्यस्थता और पारंपरिक न्यायिक व्यवस्था में कोई टकराव नहीं होना चाहिए। दोनों को समानांतर रूप से काम करना चाहिए। जमीनी स्तर पर यह भरोसा पैदा करना जरूरी है कि मध्यस्थता न सिर्फ पक्षकारों के हित में है, बल्कि देशहित में भी है। इससे अदालतों पर बोझ कम होगा और न्याय सुलभ बनेगा।

सबरीमाला सोना चोरी के आरोपी के साथ दिखे सीएम विजयन; कांग्रेस नेता ने शेयर की तस्वीर, हिरासत में लिए गए

तिरुवनंतपुरम। केरल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां कांग्रेस नेता एन. सुब्रह्मण्यन को पुलिस ने शनिवार को हिरासत में लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की, जिसमें मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सबरीमाला सोने के मामले के आरोपी उन्नीकृष्णन पोटी एक साथ दिख रहे हैं। सुब्रह्मणियन जो राज्य कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी के सदस्य हैं, उनके खिलाफ चेवयूर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

बता दें कि फोटो के कैप्शन में मुख्यमंत्री और आरोपी के कथित करीबी रिश्ते पर सवाल उठाया गया था। पुलिस ने शनिवार सुबह उनके घर जाकर बयान दर्ज किया और बाद में उन्हें पूरी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

कांग्रेस नेता ने लगाया गंभीर आरोप

सुब्रह्मणियन ने मामले में पत्रकारों से कहा कि जो फोटो उन्होंने शेयर की वह जेनरेटेड नहीं है, बल्कि यह मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी वीडियो से ली गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सीएम की आलोचना करने वालों को जेल भेज रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर के अकाउंट पर भी यही फोटो 29 नवंबर को थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

मुंबई मेयर लड़ाई में खान-पठान-बुर्का से गरमाई राजनीति, ओवैसी की पार्टी से भिड़ गए संजय राउत

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन ज्यादातर दलों के बीच गठबंधन की औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है। इस बीच मुंबई में बीएमसी का मेयर कौन बनेगा, इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। एमआईएम नेता वारिश पठान के बयान मुंबई का मेयर मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता, पर उद्धव सेना ने पलटवार किया है। उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि भारत में पहले भी मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत में जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। बीजेपी के भी के शासनकाल में भी कई राज्यों में मुस्लिम राज्यपाल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को नजर अंदाज कर देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। बता दें कि वीं में उद्धव सेना और मनसे के गठबंधन की घोषणा के दौरान राज ठाकर ने कहा कि मुंबई का मेयर हमारा और मराठी बनेगा। जबकि मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम कह चुके हैं कि मुंबई का मेयर कोई खान या पठान नहीं बनेगा।

बीएमसी चुनाव 2026 से पहले, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता वारिस पठान ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर बोलते हुए संवैधानिक सिद्धांतों का हवाला दिया और जोर देकर कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। संविधान समानता की बात करता है, और हम संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि पठान, खान, अंसारी, शेख या कुरैशी महापौर क्यों नहीं बन सकते? संविधान सभी के लिए समानता सुनिश्चित करता है। एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की महापौर बन सकती है और ईश्वर की कृपा से वह दिन अवश्य आएगा।

पठान की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईएमआईएम नेता की आलोचना की। राउत ने बताया कि भारत में पहले भी मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्होंने देश के समावेशी राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डाला। राउत ने कहा कि भारत में जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। भाजपा के शासनकाल में भी कई राज्यों में मुस्लिम राज्यपाल रहे हैं। मेरा मानना है कि इस मुद्दे को नजरअंदाज कर हमें आगे बढ़ना चाहिए।

महाराष्ट्र में कबूतरों को दाना खिलाने पर कोर्ट सख्त, लगाया 5000 रुपए का जुर्माना

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई नगर निगम ने कबूतरों से आम जनता के स्वास्थ्य को होने वाले खतरे को देखते हुए कबूतरखाने को बंद करने का फैसला किया. दादर में कबूतरखाने के अलावा अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की गई. इस फैसले से कुछ लोग नाराज हो गए. कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई राहत नहीं दी. इसके बाद भी कुछ लोग दादर आकर कबूतरों को दाना खिला रहे थे. अदालत ने दादर इलाके में रहने वाले कारोबारी नितिन शेठ को इस मामले में दोषी पाया और उन पर जुर्माना लगाया. कहा जा रहा है कि देश में इस तरह की सजा का यह पहला मामला है.

नितिन शेठ दादर इलाके में रहते हैं. वे एक व्यापारी हैं. दादर इलाके में कबूतरखाना बंद होने के बाद, वे यहां आए और कबूतरों को दाना खिलाया. इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है.

नितिन ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है. पुलिस ने बताया कि यह व्यापारी सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाना प्रतिबंधित होने के बावजूद ऐसा कर रहा था. शिकायत के आधार पर इस व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई.

5 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

इस मामले में अदालत ने व्यापारी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीवाई मिसल ने सोमवार को यह फैसला सुनाया. सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 223 (ख) के तहत सुनाई गई. यह स्पष्ट था कि व्यापारी ने जनता के स्वास्थ्य, जीवन और सुरक्षा को खतरे में डाला था. इसके अलावा, उस पर बीएनएस की धारा 271 के तहत स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बीमारी फैलाने का भी आरोप लगाया गया था.

इस फैसले में अदालत ने साफ किया है कि इस तरह की सजा पहली बार दी जा रही है. यह एक उदाहरण है. इसलिए, अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया है कि लोगों को भविष्य में ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए.

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई की थी. हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है।

महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव 2026: NCP उम्मीदवार नजीब मुल्ला का ठाणे में शक्ति प्रदर्शन, बोले- जनता का समर्थन हमारे साथ

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गईं है. चुनाव के नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए रणनीतियों पर काम कर रहे हैं. हालांकि चुनाव से पहले प्रमुख दलों के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है. ऐसे हालात में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है. पार्टियों ने अपने-अपने स्तर पर प्रचार शुरू कर दिया है.

देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने ठाणे में नमो भारत, नमो ठाणे के बैनर लगाकर चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत कर दी है. वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) की ओर से आज शाम (शनिवार, 27 दिसंबर) सांसद श्रीकांत शिंदे की जनसभा प्रस्तावित है. इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की ओर से भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला. पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव नजीब मुल्ला और सुहास देसाई ने पार्टी के घड़ी चुनाव चिन्ह पर पर्चा दाखिल करने से पहले प्रचार रैली निकाली.

राबोडी इलाके में नजीब मुल्ला ने निकाली रैली

जानकारी के मुताबिक ठाणे के राबोडी इलाके में नजीब मुल्ला के नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन रैली आयोजित की गई. ये रैली पूरे वार्ड से गुजरते हुए दरगाह पहुंची, जहां नजीब मुल्ला ने चादर चढ़ाई और फिर दुआ मांगी. इसके बाद उन्होंने राबोडी भाजी मार्केट सहित मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया. इस दौरान नजीब मुल्ला मुस्लिम महिलाओं से भी मुलाकात करते हुए उनसे दुआ और समर्थन की अपील करते नजर आए. मीडिया से बात करते हुए एनसीपी उम्मीदवार नजीब मुल्ला ने कहा हम

विकास और सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास रखते हैं. उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन हमारे साथ है और हम पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में हैं.

राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे पर फंसा पेंच

महानगर पालिका चुनावों से पहले ठाणे में इस तरह के शक्ति प्रदर्शन और रैलियों ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है. लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे का मामला अभी भी फंसा हुआ है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सीटों के बंटवारे का मामला हल नहीं हुआ है. इधर महायुति में बीजेपी और शिंदे सेना ने गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।

महायुति की तरफ से बताया गया है कि बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 150 सीटों का फैसला हो गया है. बाकी की सीटों पर बातचीत चल रही है. वहीं कांग्रेस भी प्रकाश आंबेडकर वाली वंचित विकास आघाडी के साथ गठबंधन तय नहीं है. तो वहीं शरद पवार और अजित पवार की एनसीपी किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे की तस्वीर भी फिलहाल साफ नहीं है।

15 जनवरी को होगा मतदान

बीएमसी सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं में 23 दिसंबर से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है. 31 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 2 जनवरी 2026 तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है. 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटन और अंतिम उम्मीदवार सूची का प्रकाशन होगा. 15 जनवरी को मतदान होगा, जबकि 16 जनवरी को मतगणना होगी. महापालिका चुनावों के लिए 1 जुलाई 2025 की मतदाता सूची को अंतिम और मान्य माना जाएगा. चुनाव आयोग के अनुसार इसी सूची के आधार पर मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी।

भारतीय रेल ने अगले पाँच वर्षों में प्रमुख शहरों में ट्रेनों की क्षमता दोगुनी करने की योजना बनाई

मुंबई, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, उज्जैन एवं इंदौर में यात्रा सुविधाओं में पश्चिम रेलवे द्वारा होगा विस्तार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

यात्रियों की यात्रा मांग में तीव्र एवं निरंतर वृद्धि को देखते हुए भारतीय रेल ने अगले पाँच वर्षों में प्रमुख शहरों से नई ट्रेनों के संचालन की क्षमता को दोगुना करने की योजना बनाई है। भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा रेलवे अवसंरचना का व्यापक, चरणबद्ध एवं समयबद्ध उन्नयन किया जाएगा।

वर्ष 2030 तक ट्रेनों की हैंडलिंग क्षमता दोगुनी करने के उद्देश्य से जिन कार्यों की योजना बनाई गई है, उनमें टर्मिनलों का विस्तार करते हुए अतिरिक्त प्लेटफॉर्मों का निर्माण, नई पिट लाइनों की व्यवस्था, होल्डिंग एवं स्टेबलिंग लाइनों का विकास, शंटिंग व्यवस्थाओं में सुधार, शहरी क्षेत्रों के भीतर एवं आसपास नए टर्मिनलों का निर्माण, मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव अवसंरचना का विकास तथा सिग्नलिंग उन्नयन, ट्रैफिक सुविधा कार्यों एवं मल्टी-ट्रैकिंग के माध्यम से सेक्शन क्षमता में वृद्धि शामिल है। देश के 48 प्रमुख शहरों को कवर करने वाली एक समग्र योजना पर विचार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगले पाँच वर्षों में चरणबद्ध रूप से क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि यात्रियों को शीघ्र लाभ मिल सके।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत पश्चिम रेलवे ने अपने क्षेत्राधिकार में क्षमता वृद्धि हेतु छह प्रमुख शहरों, मुंबई, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, उज्जैन एवं इंदौर को चिन्हित किया है। इन शहरों में टर्मिनल विस्तार, रखरखाव एवं स्टेबलिंग अवसंरचना के विकास तथा सेक्शन क्षमता में सुधार के माध्यम से चरणबद्ध रूप से क्षमता संवर्धन किया जाएगा, जिससे भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके।

मुंबई क्षेत्र में लंबी दूरी की ट्रेनों की क्षमता में वृद्धि

पश्चिम रेलवे मुंबई क्षेत्र में यात्रियों के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों की हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इनमें नए टर्मिनलों का निर्माण, अतिरिक्त लाइनों का विकास, नई रखरखाव सुविधाओं का सृजन, प्लेटफॉर्म विस्तार सहित विभिन्न अवसंरचनात्मक कार्य शामिल हैं।

वर्तमान में पश्चिम रेलवे मुंबई क्षेत्र से 44 लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन करती है। इन अवसंरचनात्मक कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात लगभग 65 अतिरिक्त लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन की योजना है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा ट्रेनों में प्रतिदिन लगभग 70 कोचों की वृद्धि भी प्रस्तावित है।

भीड़भाड़ कम करने एवं यात्रा परिस्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से मुंबई सेंट्रल-दहानू रोड सेक्शन पर लगभग 6857 करोड़ की कुल लागत से लाइन क्षमता बढ़ाने के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। MUTP-II के अंतर्गत 30 किलोमीटर लंबी मुंबई सेंट्रल-बोरीवली छठी लाइन परियोजना 919 करोड़ की लागत से दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। चरण-I के अंतर्गत खार-कांदिवली खंड का कमीशनिंग पूर्ण हो चुका है, जबकि कांदिवली-बोरीवली खंड का कार्य अंतिम चरण में है और इसके जनवरी 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर बांद्रा टर्मिनस से आने-जाने वाली ट्रेनों के लिए इस सेक्शन पर दो समर्पित लाइनें उपलब्ध होंगी, जिससे उपनगरीय एवं मुख्य लाइन यातायात का बेहतर पृथक्करण संभव होगा तथा मुंबई क्षेत्र से अतिरिक्त लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, ?2184 करोड़ की लागत से बोरीवली-विरार 5वीं एवं 6वीं लाइन परियोजना तथा 3578 करोड़ की लागत से विरार-दहानू रोड 3री एवं 4थी लाइन परियोजना पर भी तीव्र गति से कार्य प्रगति पर है। इनके पूर्ण होने से संबंधित सेक्शनों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता उपलब्ध होगी, जिससे लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन के लिए अधिक क्षमता सृजित होगी। साथ ही, 176 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन नायगांव-जुईचंद्रा डबल कॉर्ड लाइन परियोजना वसई रोड पर लोको रिवर्सल की आवश्यकता को समाप्त करते हुए कोंकण रेलवे की ओर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे पश्चिमी उपनगरों से कोंकण, गोवा एवं उससे आगे के क्षेत्रों के लिए नई ट्रेन सेवाओं का मार्ग प्रशस्त होगा। सामूहिक रूप से, ये सभी पहलें समयपालन में सुधार, भीड़ में कमी तथा यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करेंगी।

लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए जोगेश्वरी में तीन प्लेटफॉर्मों वाला एक नया टर्मिनस निर्माणाधीन है, जिसका कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है और इसके अगले वर्ष के मध्य तक पूरा होने की संभावना है। इसी प्रकार, वसई रोड स्टेशन पर भी लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए एक नया टर्मिनस विकसित किया जा रहा है, जहां दो नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसका कार्य दिसंबर 2027 तक पूर्ण होने की संभावना है। नए टर्मिनलों के अतिरिक्त, मौजूदा टर्मिनलों–मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस एवं दादर–पर भी नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा रखरखाव सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है।

कपड़े से ढका चेहरा और रस्सी से बंधे हाथ; नगर निमग चुनाव में गैंगस्टर बना प्रत्याशी, किया नामांकन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। चेहरे पर काले कपड़े से ढके और हाथ बंधे हुए, अपने पोते की कथित हत्या के आरोप में जेल में बंद स्थानीय गैंग लीडर बंदू अंडेकर को शनिवार को यहां एक सरकारी दफ्तर ले जाया गया, जहां उन्होंने पुलिस सुरक्षा के बीच पुणे में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया।

पुणे की राजनीति में शनिवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने कानून, अपराध और चुनावी प्रक्रिया तीनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया। चेहरे पर काला कपड़ा, हाथ रस्सी से बंधे और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच एक स्थानीय गैंग लीडर जेल से सीधे नामांकन केंद्र पहुंचा। यह वही शख्स है, जो अपने ही पोते की हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में बंद है, लेकिन अब उसने आगामी नगर निगम चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।

जेल में बंद आरोपी ने दाखिल किया नामांकन

पोते की हत्या के मामले में जेल में बंद स्थानीय गैंग लीडर बंडू आंडेकर को पुणे की विशेष मकोका अदालत ने सशर्त अनुमति दी थी। इसी अनुमति के आधार पर शनिवार को उसे पुलिस वैन से नामांकन केंद्र लाया गया। काले कपड़े से चेहरा ढका हुआ था और हाथ रस्सी से बंधे थे। इसके बावजूद उसने नामांकन केंद्र के अंदर जाते समय अपने समर्थन में नारे लगाए। आंडेकर ने निर्दलीय

उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया।

अदालत की अनुमति से परिवार ने भी भरे पर्चे

अदालत के आदेश के तहत बंडू आंडेकर की बहू लक्ष्मी आंडेकर और बहू सोनाली आंडेकर ने भी नामांकन दाखिल किया। ये दोनों भी उसी हत्या मामले में आरोपी हैं और न्यायिक हिरासत में हैं। तीनों ने पुणे नगर निगम के भवानी पेठ वार्ड कार्यालय में अपने-अपने पर्चे भरे। उनके वकील मिथुन चव्हाण ने बताया कि सभी ने अदालत की शर्तों का पालन करते हुए नामांकन प्रक्रिया पूरी की।

15 जनवरी को होने हैं नगर निकाय चुनाव

महाराष्ट्र में पुणे सहित 28 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को प्रस्तावित हैं। ऐसे समय में जेल में बंद आरोपियों द्वारा नामांकन दाखिल किया जाना राजनीतिक और कानूनी बहस को जन्म दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र नामांकन केंद्र के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो।

पोते की हत्या से जुड़ा है पूरा मामला

यह पूरा मामला 5 सितंबर को नाना पेठ इलाके में हुई एक सनसनीखेज हत्या से जुड़ा है। बंडू आंडेकर के पोते आयुष कोमकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आयुष, गणेश कोमकर का बेटा था, जो पहले से एक अन्य हत्या मामले में आरोपी है। गणेश पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगरसेवक और बंडू आंडेकर के बेटे वनराज आंडेकर की हत्या का आरोप है। इस तरह यह मामला आपसी दुश्मनी और हिंसा की लंबी कड़ी से जुड़ा हुआ है।

15 अन्य आरोपियों के साथ जेल में बंद

बंडू उर्फ सूर्यकांत राणोजी आंडेकर (70), लक्ष्मी उदयकांत आंडेकर (60) और सोनाली वनराज आंडेकर (36) नाना पेठ इलाके के निवासी हैं। इनके साथ कुल 15 अन्य लोग भी आयुष की हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। सभी पर हत्या और साजिश से जुड़े गंभीर आरोप हैं। इसके बावजूद चुनावी मैदान में उतरना, स्थानीय राजनीति की जटिल और विवादित तस्वीर पेश करता है।

सानपाड़ा के हुतात्मा बाबू गेनु मैदान में बिना इजाज़त गाड़ी पार्किंग के खिलाफ़ कार्रवाई करके मैदान की सफ़ाई की

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

चुनाव फ़ैसले के अधिकारी के ऑफ़िस का इंस्पेक्शन करते समय, मनपा कमिश्नर डॉ. कैलाश शिंदे ने देखा कि तुर्भे डिवीज़न के सानपाड़ा में हुतात्मा बाबू गेनु मैदान में गैर-कानूनी तरीके से गाड़ियां पार्क की गई थीं और वहां बहुत ज़्यादा कचरा था। वहां रुककर, उन्होंने तुरंत संबंधित डिपार्टमेंट के छठे कमिश्नर, श्री सागर मोरे को बुलाया और उन्हें तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

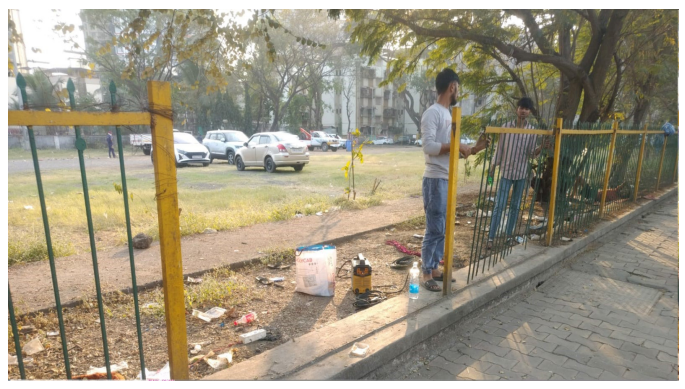

इसके अनुसार, मनपा की अतिक्रमण विरोधी टीम ने कार्रवाई की और गाड़ियों को ज़ब्त करके डंपिंग ग्राउंड ले गई। इसी तरह, मैदान की सफ़ाई के लिए तुरंत एक टीम भेजी गई और मैदान की सफ़ाई की गई। इसी तरह, मैदान के गेट बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई भी मैदान में अपनी गाड़ियां पार्क न कर सके। यह मैदान बच्चों के खेलने के लिए खुला रहेगा। मनपा यह घोषणा कर रही है कि भविष्य में मैदान में गैर-कानूनी तरीके से पार्किंग करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पश्चिम रेलवे

विभिन्न कार्य

डिविजनल रेलवे मैनेजर (WA), वेस्टर्न रेलवे, छठी मंजिल, इंजीनियरिंग विभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400 008 ई-टेंडर आमंत्रित करते हैं- नोटिस संख्या: BCT/25-26/290 दिनांक 24/12/2025। **कार्य और स्थान: विरार-जोरावासन सेक्शन: करंबेली:-** ADEN/वलसाड के अधिकार क्षेत्र में करंबेली में गुड्स प्लेटफॉर्म, अप्रोच रोड, प्लेटफॉर्म-1 के पश्चिम की ओर FOB का विस्तार और पुलिया संख्या-267, 268 और 269 का विस्तार प्रदान करना। **कार्य की अनुमानित लागत:** 17,61,35,627.21 **EMD:** 10,30,700/-। **जमा करने की तारीख और समय:** 20.01.2026 15:00 बजे तक। खोलने की तारीख और समय: 20.01.2026 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 0941

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

मध्य रेल

नागपुर डिवीजन

ई-निविदा सूचना

खुली निविदा सूचना संख्या: सीनियर डीएमएम नागपुर/95255793 दिनांक 26/12/2025

निविदा बंद होने की दिनांक: 15.01.2026 समय: सुबह 1.30 बजे

निविदा फ़ाइल संख्या: 95255793. संक्षेप में विवरण: 1) RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर RDSO/SPN/153/2023 रिवीजन 5.0 या लेटेस्ट संशोधन के अनुसार मौजूदा CLS हाउसिंग में रेट्रोफिटेबल रूट LED सिग्नल लाइटिंग यूनिट की सप्लाई। **मात्रा:** 600 नग। **2)** कॉलिंग ऑन LED सिग्नल लाइटिंग यूनिट 110V AC की सप्लाई, जो मौजूदा CLS हाउसिंग में रेट्रोफिटेबल हो और RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर RDSO/SPN/153/2023 (Rev. 5.0) के अनुसार लेटेस्ट संशोधन के साथ AC LED ECR के साथ कम्पैटिबल हो। **मात्रा:** 150 नग। **3)** शंट सिग्नल एस्पेक्ट LED सिग्नल यूनिट, 110V AC की सप्लाई, जिसमें LED लैंप प्रूविंग रिले को चलाने के लिए लैंप प्रूविंग आउटपुट हो, पूरी यूनिट RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर RDSO/SPN/153/2023 (Rev. 5.0) या लेटेस्ट संशोधन या LED सिग्नल एस्पेक्ट्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन के अनुसार होनी चाहिए। वेबसाइट का पता जहां से निविदा की विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर देखा जा सकता है **www.ireps.gov.in**.

व.मं.सा.प्र., नागपुर 42

रेल्वे फाटक को बंद स्थिति में पार करना मना है

हिंदी नहीं बोलती थी बेटी, मां ने गला दबाकर मार डाला दिल दहला देगा नवी मुंबई का ये मर्डर केस

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

एक बच्चा अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित अपनी मां के आंचल में समझता है, लेकिन महाराष्ट्र केनवी मुंबई में एक हैवान मां ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी. उसने अपनी 6 साल की मासूम बेटी को गला दबाकर मार डाला. वह भी सिर्फ इस बात पर कि बच्ची हिंदी में बात करती थी. उसकी मां उसे मराठी बोलने के लिए कहती थी. हत्या वाले दिन भी जब बेटी ने हिंदी में बात की तो मां को गुस्सा आ गया और मां ने उसे मार डाला.

ये मामला नवी मुंबई में पनवेल के कलंबोली से सामने आया है. आरोपी मां की पहचान सुप्रिया प्रमोद म्हामुणकर के रूप में हुई है, जो बेटी के जन्म के बाद से ही उसे पसंद नहीं करती थी. इसकी वजह ये थी कि वह बेटी नहीं बल्कि, बेटा चाहती थी, लेकिन जब उसके बेटी हो गई तो वह तनाव में रहने लगी और बच्ची से प्यार भी नहीं करती थी. अब उसने बेटी की हत्या ही कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

3 दिन की हिरासत में भेजा गया

पुलिस ने सुप्रिया प्रमोद को शुक्रवार को पनवेल कोर्ट में पेश किया और उसे 3 दिन की हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि महिला अपनी बेटी से प्यार नहीं करती थी. सुप्रिया की बेटी हिंदी में बात करती थी. ये बात भी उसे जरा पसंद नहीं थी. हिंदी बोलने पर भी सुप्रिया बेटी को डांटती रहती थी. बेटी की हत्या करने के बाद उसने पहले पुलिस को बताया कि बेटी की बीमारी से मौत हो गई।

ऐसे में शुरुआत में बच्ची की मौत को नॉर्मल समझा गया, लेकिन फिर पनवेल उप-जिला अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों को बच्ची की मौत को लेकर शक हुआ. उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी. इसके बाद में कराए गए पोस्टमॉर्टम में खुलासा हुआ कि बच्ची की मौत गला दबाए जाने से हुई थी. जांच के दौरान बच्ची की मां इस मामले में मुख्य संदिग्ध के रूप में सामने आई।

मुंह और नाक दबाई, फिर गला घोंट दिया

जानकारी के मुताबिक सुप्रिया पिछले साल से डिप्रेशन में थी और साइकेट्रिस्ट से इलाज भी करा रही थी।

पश्चिम रेलवे

स्टोर्स डिपो के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

डिविजनल रेलवे मैनेजर (WA), वेस्टर्न रेलवे, छठी मंज़िल, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400 008, ई-टेंडर नोटिस नंबर: एऊ/25-26/291 तारीख 24/12/2025 जारी करते हैं। **काम और जगह:** महालक्ष्मी (GSD) और मुंबई सेंट्रल: स्टोर्स डिपो के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार (कम्पोज़िट टेंडर)। **काम की अनुमानित लागत:** 8,18,66,019.44 रुपये। **ईएमडी:** 5,59,300/- रुपये। **जमा करने की तारीख और समय:** 20.01.2026 तक 15:00 बजे तक। **खोलने की तारीख और समय:** 20.01.2026 को 15:30 बजे। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 0940

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

देवेंद्र फडणवीस का बड़ा दावा, बोले- Mahayuti में जल्द सुलझेगा गतिरोध, गठबंधन तय

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

आगामी महीने होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि महायुति गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है, जिससे गतिरोध के संभावित समाधान का संकेत मिलता है। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि बीएमसी चुनावों के लिए गठबंधन निश्चित रूप से होगा और इसमें किसी भी प्रकार की बाधा से इनकार किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महायुति गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बहुत सकारात्मक चर्चा चल रही है। मुझे उम्मीद है कि यह गतिरोध जल्द ही दूर हो जाएगा। गठबंधन निश्चित रूप से होगा और इसमें कोई बाधा नहीं होगी। फडणवीस की यह टिप्पणी शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीएमसी चुनावों के

लिए गठबंधन की पृष्ठभूमि में आई है। इस महीने की शुरुआत में, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि महायुति गठबंधन आगामी चुनावों में स्थानीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक साथ चुनाव लड़ेगा और इस बात पर जोर दिया था कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य उनके अभियान का आधार होंगे। शिंदे ने मीडिया से कहा कि हम स्थानीय और वरिष्ठ दोनों स्तरों पर महायुति के रूप में चुनाव लड़ेंगे। पिछले साढ़े तीन वर्षों में हमने कई विकास परियोजनाएं पूरी की हैं और उन्हें जनता के सामने प्रस्तुत किया है। हम विकास और प्रगति के अपने एजेंडे के बल पर यह चुनाव लड़ेंगे। जनता समझदार है। इस सप्ताह की शुरुआत में, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने आगामी बीएमसी चुनावों से पहले अपने गठबंधन की घोषणा की। वर्षों से अलग रहे ठाकरे बंधुओं के आगामी चुनावों से ठीक पहले इस राजनीतिक पुनर्मिलन ने राजनीतिक जगत में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं।

इन घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने केवल वोट हासिल करने के लिए राष्ट्रविरोधी और हानिकारक गतिविधियों में शामिल समूहों के साथ गठबंधन करके अपना असली चरित्र दिखाया है, और चेतावनी दी कि जनता इसका कड़ा जवाब देगी।

गीता-ज्ञान से आलोकित हुआ कांदिवली

श्रीमद् भागवत ज्ञानयज्ञ के चतुर्थ दिवस पर उमड़ा श्रद्धा-सैलाब

मुंबई। कांदिवली (पूर्व) स्थित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदान में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञानयज्ञ के चतुर्थ दिवस पर आध्यात्मिक चेतना अपने उत्कर्ष पर रही। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानन्द तीर्थ जी महाराज के ओजस्वी प्रवचनों से हजारों श्रद्धालु गीता-ज्ञान से अनुप्राणित हुए।

'सुविधाएँ हैं, पर शांति नहीं' – स्वामी नारायणानन्द तीर्थ

स्वामी जी ने समकालीन जीवन की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भौतिक प्रगति के बीच मनुष्य मानसिक अशांति से जूझ रहा है। उन्होंने गीता के समत्व-संदेश को रेखांकित करते हुए कहा–

'सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।' (गीता 2.38)

गीताः जीवन का शाश्वत मार्गदर्शक

स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि श्रीमद्भगवद्गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलित जीवन-दर्शन है–

'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।' (गीता 2.47)

ज्ञान की महिमा

ज्ञान को आत्मोन्नति का आधार बताते हुए उन्होंने कहा–

'न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।' (गीता 4.38)

शरणागति का संदेश

अहंकार-त्याग और ईश्वर-समर्पण का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी ने कहा–

'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।' (गीता 18.66)

युवाओं को विशेष संदेश

प्रतिस्पर्धा और दबाव के युग में आत्मबल का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा–

'उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्।' (गीता 6.5)

आयोजन समिति के अनुसार ज्ञानयज्ञ में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और परिसर में शांति, अनुशासन एवं भक्ति का वातावरण बना हुआ है। आयोजन को सफल बनाने में एडवोकेट जे. डी. सिंह, श्री राममणि मिश्र, श्री ओमप्रकाश सिंह, श्री हरिश्चंद्र शुक्ल, प्रमोद दुबे, डॉ. दिनकर दुबे, संचित यादव, अनिल पांडेय, सूरज प्रताप सिंह देवड़ा सहित अनेक कार्यकर्ता सक्रिय रहे।

नववर्ष का संकल्प

समापन में स्वामी जी ने संदेश दिया–

'मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।' (गीता 18.65)

अर्थात नया वर्ष आत्मशुद्धि और चरित्र-निर्माण के संकल्प के साथ आरंभ हो।

प्रो. दयानंद तिवारी
प्रवक्ता, काशी धर्म पीठ
मो.: 9987123330
(कृपया प्रकाशनार्थ)

श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर तीन महीने के लिए बंद रहेगा, पुणे के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भक्तों से सहयोग की अपील की

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पुणे। भक्तों की सुरक्षा पक्का करने और श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर में असेंबली हॉल और वॉकवे का कंस्ट्रक्शन प्लान के हिसाब से और समय पर पूरा करने के लिए, श्री क्षेत्र भीमाशंकर संस्थान ने महाशिवरात्रि के समय को छोड़कर, 9 जनवरी, 2026 से अगले तीन महीनों के लिए भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर बंद करने का फैसला किया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितेंद्र डुडी ने भक्तों से सहयोग करने की अपील की है।

राज्य सरकार ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक खास डेवलपमेंट प्लान को मंज़ूरी दी है। इस प्लान के एक बहुत ज़रूरी फेज़ को लागू करने और असल कंस्ट्रक्शन के समय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, 23 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, श्री क्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान संस्थान के ट्रस्टी, लोकल दुकानदार और श्री. भीमाशंकर गांववालों की मौजूदगी में हुई एक जॉइंट मीटिंग में यह तय किया गया कि 9 जनवरी से मंदिर को तीन महीने के लिए टेम्परी तौर पर बंद कर दिया जाएगा (12 से 18 फरवरी, 2026 तक महाशिवरात्रि का समय छोड़कर)। हालांकि, भक्तों की सुविधा के लिए, महाशिवरात्रि के दौरान मंदिर दर्शन के लिए खुला रहेगा।

साल 2027 में, सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक के त्र्यंबकेश्वर में लगेगा। प्रयागराज में हुए महाकुंभ 2025 के अनुभव के आधार पर, यह संभावना है कि कुंभ मेले के दौरान नासिक-त्र्यंबकेश्वर आने वाले लाखों भक्त दर्शन के लिए श्री क्षेत्र भीमाशंकर आएंगे। इसे देखते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन का पहला मकसद कुंभ मेले से पहले ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मीटिंग हॉल, सुरक्षित एंट्री-एग्जिट सिस्टम और भीड़ कंट्रोल के काम समय पर पूरे करना है। काम के नेचर और स्कोप को देखते हुए, भक्तों की सेफ्टी बनाए रखने के अलावा, काम को प्लान्ड और टाइम-बाउंड तरीके से पूरा करना ज़रूरी है, इसलिए मंदिर परिसर भक्तों के लिए टेम्परी तौर पर बंद रहेगा।

हालांकि मंदिर दर्शन के लिए बंद है, लेकिन श्री भीमाशंकर की रोज़ाना की पूजा, अभिषेक और धार्मिक रस्में ट्रेडिशन के हिसाब से और तय समय पर जारी रहेंगी। डायरेक्ट दर्शन के टाइम के दौरान, भक्तों को मंदिर परिसर में एंट्री करने या डायरेक्ट दर्शन सर्विस लेने की इजाज़त नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ऑथराइज़्ड अधिकारियों और भीमाशंकर गांववालों को छोड़कर, किसी को भी श्री क्षेत्र भीमाशंकर एरिया में एंट्री करने की इजाज़त नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री डुडी ने यह भी अपील की है, 'श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर का डेवलपमेंट भक्तों की लंबे समय तक सेफ्टी, सुविधाओं और सहूलियत के लिए बहुत ज़रूरी है। सिंहस्थ कुंभ मेले के बैकग्राउंड में, मंदिर अथॉरिटी ने इन कामों को प्लान्ड और टाइम-बाउंड तरीके से पूरा करने के लिए मंदिर को टेम्परी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। भक्तों और लोकल लोगों को इस फैसले को सीरियसली लेना चाहिए और मंदिर अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कोऑपरेट करना चाहिए।'

निकाय चुनाव में एनसीपी की एकता पर प्रश्नचिन्हः अजीत-शरद पवार के बीच 'घड़ी' बनाम 'तुरही' का पेंच

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुट पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम चुनावों में गठबंधन करने में विफल रहे हैं। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और एनसीपी-एसपी दोनों ही स्थानीय निकाय चुनाव मिलकर लड़ने के इच्छुक थे और पिछले कुछ दिनों में दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं ने कई बैठकें की थीं। हालांकि, एनसीपी ने एक शर्त रखी थी कि एनसीपी-एसपी के सभी उम्मीदवार उसके 'घड़ी' चिन्ह पर चुनाव लड़ें, जो शरद पवार गुट को स्वीकार्य नहीं था। सूत्रों के अनुसार, एनसीपी-एसपी ने अजीत पवार गुट को बताया कि उसके उम्मीदवार केवल उसके 'तुरही' चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे।

हालांकि दोनों गुटों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, सूत्रों का मानना है कि उनके बीच बातचीत जारी रहेगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने शुक्रवार रात पिंपरी-चिंचवाड़ में एनसीपी-

एसपी नेता आज़म पानसरे से मुलाकात कर गठबंधन की संभावना पर चर्चा की थी। पानसरे ने कहा कि अजीत पवार लंबे समय बाद मुझसे मिलने आए। हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। हम (एनसीपी, एसपी और एनसीपी के बीच) गठबंधन करना चाहते हैं... उन्होंने मुझे बताया कि जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा।

2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, अजीत पवार और कई अन्य नेताओं के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने के बाद एनसीपी में फूट पड़ गई थी। बाद में, भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी घोषित किया और उसे मूल 'घड़ी' का चुनाव चिन्ह दिया। हालांकि, पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम चुनावों के लिए दोनों पार्टियां एक बार फिर से गठबंधन करने पर विचार कर रही हैं। एनसीपी के इस संभावित गठबंधन को देखते हुए, कांग्रेस ने कहा है कि वह महाराष्ट्र में हाल के घटनाक्रमों पर नजर रख रही है और शरद पवार के फैसले का स्वागत करेगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-यूबीटी ने भी इसी तरह का बयान दिया है।

सिडको द्वारा चलाए जा रहे सामूहिक आवास परियोजनाओं के निर्माण स्थल परङ्ङमानक संचालन प्रक्रियाओं के सख्त कार्यान्वयन के संबंध में नोटिस

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवी मुंबई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, नवी मुंबई नगर निगम द्वारा विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, और इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नगर निगम क्षेत्र के भीतर चल रहे निर्माण स्थलों पर प्रदूषण रोकथाम उपायों को सख्ती से लागू करने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

इसके लिए, नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के निर्देशों के अनुसार, निर्माण स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ब्लास्टिंग के लिए पालन की जाने वाली 'मानक संचालन प्रक्रिया' की घोषणा की गई है और निर्माण परियोजना स्थलों पर वायु और ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में 01/08/2024 को एक सर्कुलर जारी किया गया है। साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त ध्वनि और वायु प्रदूषण के संबंध में किए जाने वाले उपायों के संबंध में 28/11/2025 को एक आदेश जारी किया है।

तदनुसार, आयुक्त ने NMUMPA क्षेत्र के डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स के साथ एक विशेष बैठक की थी और उन्हें मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था। हालांकि, तुर्भे डिवीजन के निरीक्षण दौरे के दौरान, यह देखा गया कि जुईनगर रेलवे स्टेशन के पास, सेक्टर 11, सानपाड़ा में सिडको द्वारा चलाए जा रहे सामूहिक आवास परियोजना के निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं किया जा रहा था। इसी तरह, यह बताया गया है कि प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 19, वाशी में सिडको द्वारा चलाए जा रहे आवास परियोजना के निर्माण स्थल पर भी मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। तदनुसार, एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि उक्त प्लॉटों पर वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार उचित उपाय किए जाएं और किए गए उपायों की रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर नवी मुंबई नगर निगम के नगर नियोजन विभाग को प्रस्तुत की जाए। तदनुसार, यदि किए गए उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो निर्माण कार्य को निलंबित करने के संबंध में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

नवी मुंबई नगर निगम हवा की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दे रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई कर रहा है।

सेंट्रल रेलवे - कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

'बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने और भीड़भाड़ कम करने के लिए हम प्रमुख शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार कर रहे हैं। इस कदम से रेलवे नेटवर्क अपग्रेड होगा और देश भर में कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा' - श्री अश्विनी वैष्णव, रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री।

यात्रा की मांग में तेजी से लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए, अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों से नई ट्रेनों को शुरू करने की क्षमता को मौजूदा स्तर से दोगुना करने की आवश्यकता है।

आने वाले वर्षों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा।

इन शहरों में वर्ष 2030 तक ट्रेनों को शुरू करने की क्षमता को दोगुना करने के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगेः

मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं के साथ बढ़ाना

शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनलों की पहचान करना और उनका निर्माण करना

रखरखाव सुविधाएं, जिसमें मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स शामिल हैं

विभिन्न बिंदुओं पर बढ़ी हुई ट्रेनों को संभालने के लिए आवश्यक ट्रैफिक सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग अपग्रेडेशन और मल्टीट्रैकिंग के साथ सेक्शनल क्षमता बढ़ाना

टर्मिनलों की क्षमता बढ़ाने की योजना बनाते समय, टर्मिनलों के आसपास के स्टेशनों पर भी विचार किया जाएगा ताकि क्षमता समान रूप से संतुलित हो। उदाहरण के लिए, पुणे के लिए, हडपसर, खड़की और आलंदी को क्षमता बढ़ाने के लिए विचार किया गया है, साथ ही पुणे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और स्टेबलिंग लाइनें भी बढ़ाई जाएंगी।

उपरोक्त कार्य उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों तरह के ट्रैफिक के लिए किया जाएगा, जिसमें दोनों सेगमेंट की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। 48 प्रमुख शहरों के लिए एक व्यापक योजना पर विचार किया जा रहा है। इस योजना में समयबद्ध तरीके से ट्रेन-हैंडलिंग क्षमता को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित, प्रस्तावित या पहले से स्वीकृत कार्य शामिल होंगे।

हालांकि 2030 तक क्षमता को दोगुना करने की योजना है, लेकिन उम्मीद है कि अगले पांच वर्षों में क्षमता धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी, जिससे क्षमता वृद्धि के लाभ तुरंत मिल सकें।

इससे आने वाले वर्षों में ट्रैफिक की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह योजना कार्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करेगी, यानी तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक।

प्रस्तावित योजनाएं विशिष्ट होंगी, जिनमें स्पष्ट समय-सीमा और परिभाषित परिणाम होंगे। हालांकि यह एक्सरसाइज़ खास स्टेशनों पर फोकस करती है, लेकिन हर ज़ोनल रेलवे से कहा गया है कि वे अपने डिवीजनों में ट्रेन हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने की योजना बनाएं, ताकि न सिर्फ टर्मिनल कैपेसिटी बढ़े, बल्कि स्टेशनों और यार्ड में सेक्शनल कैपेसिटी और ऑपरेशनल दिक्कतों को भी प्रभावी ढंग से हल किया जा सके।

ओवैसी की पार्टी में बवाल, कैंडिडेट को लेकर दो गुटों में जमकर हुई मारपीट

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर के किराडपुरा इलाके में AIMIM पार्टी के दो गुटों के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला. वार्ड नंबर 12 से मोहम्मद इसरार को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया था. इस फैसले की खुशी में उनके समर्थकों ने एक भव्य रैली निकाली. हालांकि, जैसे ही यह रैली किराडपुरा इलाके में पहुंची, पार्टी के दूसरे गुट ने इसका विरोध किया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया और पार्टी के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई।

इस टकराव की मुख्य वजह यह थी कि वार्ड नंबर 12 से AIMIM के हाजी इसाक भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे. पार्टी द्वारा मोहम्मद इसरार के नाम पर मुहर लगने से हाजी इसाक के समर्थक नाराज हो गए थे. जैसे ही इसरार समर्थकों की रैली किराडपुरा पहुंची, हाजी इसाक के समर्थकों ने उसे रोक दिया।

पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों गुटों के बीच हाथापाई शुरू हो गई.

कैंडिडेट को लेकर दो गुटों में मारपीट

बता दें कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं. दो दिन पहले ही छ्छ्छ के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने चुनाव के लिए आठ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था. उनके ऐलान के बाद ही कई दावेदारों में असंतोष देखा जा रहा था. इसी असंतोष की वजह से यह हंगामा हुआ और पार्टी के दो गुट आपस में भिड़ गये।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहले नारेबाजी से शुरुआत हुई फिर यह मामला हाथापाई तक पहुंच गया. गुस्साए दावेदारों के समर्थकों ने रैली में जा रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया और कैंडिडेट के साथ मारपीट की।

नाराज पार्टी समर्थकों ने मचाया हंगामा

इस दौरान विक्षुब्ध दावेदारों ने कहा कि यदि पार्टी अपने फैसले पर दोबारा विचार नहीं करती है तो किराडपुरा इलाके से पार्टी का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा. स्थिति बिगड़ते देखकर उम्मीदवार को अपने समर्थकों के साथ भागने के लिए बाध्य होना पड़ा।

टर्मिनेटिंग / ओरिजिनेटिंग ट्रेन की सुविधा के साथ उत्राण स्टेशन का किया जा रहा है विकास, भारतीय रेल की अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों में रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता दोगुनी करने की योजना

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

यात्रा की मांग में लगातार हो रही तीव्र वृद्धि को देखते हुए, भारतीय रेल द्वारा अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों की नई रेल गाड़ियों के संचालन की क्षमता को वर्तमान स्तर से दोगुना करने की योजना है। आगामी वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। इस दिशा में वर्ष 2025 -26 के दौरान वडोदरा मंडल के प्रतापनगर स्टेशन पर दो नए प्लेटफार्म का निर्माण किया गया। उत्राण स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 3 एवं 4 के विस्तार के साथ अमृत भारत स्टेशन के सभी कार्य पूरे कर लिए गए है। टर्मिनेटिंग / ओरिजिनेटिंग ट्रेन की सुविधा के साथ उत्राण स्टेशन का विकास किया जाएगा, जिसमे नए हाई लेवल प्लेटफार्म का निर्माण, अप दिशा के प्लेटफार्म के विस्तार और अन्य यात्री सुविधाओं के कार्य शामिल है।

वडोदरा मंडल पर शॉर्ट टर्म यानि अगले दो वर्ष के अंतर्गत रानोली स्टेशन पर 2 पिट लाइनों एवं एक स्टेब्लिंग लाइन का निर्माण तथा उत्राण स्टेशन पर 2 नए प्लेटफार्मों का निर्माण किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, लॉन्ग टर्म यानि 3 से 5 वर्ष की योजना के अंदर प्रतापनगर स्टेशन पर 1 पिट लाइन एवं 1 स्टेबलिंग लाइन का निर्माण प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त प्रतापनगर और उत्राण में कोचिंग क्षमता बढ़ाने के लिए कोचिंग टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा।

वर्ष 2030 तक रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता को दोगुना करने के उद्देश्य से भारतीय रेल द्वारा अधोसंरचना विकास के महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिनमेंनिम्न कार्य शामिल होंगेः

मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं से सुसज्जित करना।

शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनलों की पहचान और निर्माण करना।

मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव सुविधाएं।

विभिन्न स्थानों पर रेल गाड़ियों की बढ़ती संख्या की व्यवस्था करने के लिए यातायात सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग उन्नयन और मल्टीट्रैकिंग के माध्यम से अनुभागीय क्षमता में वृद्धि करना।

केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस सम्बन्ध में कहा, 'हम यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए विभिन्न शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार कर रहे हैं और अनुभागीय एवं परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इस कदम से हमारे रेलवे नेटवर्क का उन्नयन होगा और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार होगा।'

सम्पादकीय

बच्चों की तस्करी और इंसाफ़ का टेस्ट

आज भारत में बच्चों की तस्करी सिर्फ़ एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि यह एक अच्छी तरह से ऑर्गनाइज़्ड, कई लेयर वाला और ऑर्गनाइज़्ड क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है। यह क्राइम कमज़ोर सामाजिक-आर्थिक ढाँचों में जड़ें जमा लेता है जहाँ गरीबी, अनपढ़ता, विस्थापन, जेंडर इनइक्वालिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव उदासीनता एक साथ मौजूद हैं। बच्चों की तस्करी का खौफ़नाकपन सिर्फ़ इस बात में नहीं है कि बच्चे शोषण का शिकार होते हैं, बल्कि इस बात में भी है कि यह क्राइम कानून और न्यायिक प्रक्रिया की सीमाओं का बड़ी कुशलता से फ़ायदा उठाता है। नतीजतन, कड़े कानूनी नियमों और इंटरनेशनल ज़िम्मेदारियों के बावजूद, भारत में बच्चों की तस्करी के मामलों में सज़ा की दर चिंताजनक रूप से कम है।

बच्चों की तस्करी को 'लेयर वाला ऑर्गनाइज़्ड क्राइम' कहना सिर्फ़ एक थ्योरेटिकल शब्द नहीं है, बल्कि यह इसके मैकेनिज़्म के असली नेचर को दिखाता है। इस क्राइम में आमतौर पर कोई एक सेंट्रल ऑपरेटर शामिल नहीं होता, बल्कि कई इंडिपेंडेंट लेकिन एक-दूसरे को पूरा करने वाली एंटिटीज़ शामिल होती हैं। रिक्रूटर अक्सर लोकल लेवल पर काम करते हैं, बच्चों या उनके माता-पिता को पढ़ाई, नौकरी, बेहतर ज़िंदगी या शादी के झूठे वादे करके फुसलाते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एजेंट, शेल्टर नेटवर्क, नकली डॉक्यूमेंट, और आखिर में, अलग-अलग लेवल पर काम करने वाले शोषण करने वाले लोग या ऑर्गनाइज़ेशन आते हैं। इन एंटिटीज़ के बीच सीधा कॉन्टैक्ट बहुत कम होता है, जिससे पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को एक करना और कोर्ट के सामने पेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

क्रिमिनल्स के लिए इस लेयर्ड स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हर लिंक खुद को एक खास रोल तक लिमिटेड दिखा सकता है। कुछ लोग बस खुद को 'फैसिलिटेटर' के तौर पर दिखाते हैं, दूसरे 'ब्रोकर' के तौर पर, और दूसरे 'एम्प्लॉयर' के तौर पर, इस तरह अपने क्रिमिनल इंटेंशन को छिपाते हैं। नतीजतन, प्रॉसिक्यूटर के लिए क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी, कॉमन इंटेंशन और ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम को साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह कॉम्प्लेक्सिटी तब और बढ़ जाती है जब ट्रैफिकिंग इंटरस्टेट या इंटरनेशनल हो जाती है, जहाँ अलग-अलग राज्यों के कानून, पुलिस सिस्टम और ज्यूडिशियल प्रोसेस कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं।

आजकल के समय में, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इस क्राइम को और भी ज़्यादा इनविज़िबल बना दिया है। एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सीक्रेट मैसेजिंग ऐप और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के ज़रिए, ट्रैफिकर न केवल बच्चों के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं बल्कि सबूत भी जल्दी से मिटा देते हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन के तरीके नाकाफी साबित होते हैं, और प्रॉसिक्यूशन का बोझ आखिर में विक्टिम की गवाही पर पड़ता है। यहीं से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों में सबूतों की असली समस्या शुरू होती है। नाबालिग पीड़ित अक्सर डर, ट्रॉमा, सोशल स्टिग्मा और पैसे की तंगी की वजह से खुलकर बात नहीं कर पाते। लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक टॉर्चर उनकी याददाश्त पर असर डालता है, जिससे स्वाभाविक रूप से उनकी गवाही में अंतर, कमियां और विरोधाभास आ जाते हैं। इसके बावजूद, पारंपरिक न्यायिक तरीकों ने इन अंतरों को गवाही के भरोसे न होने का सबूत माना है।

पहले से, भारतीय न्याय व्यवस्था ने अक्सर ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से साथी माना है। खासकर यौन शोषण या गैर-कानूनी काम से जुड़े मामलों में, यह माना जाता था कि पीड़ित ने हालात से समझौता किया या किसी न किसी लेवल पर अपराध में हिस्सा लिया। इस तरीके की वजह से उनकी गवाही की और पुष्टि की ज़रूरत पड़ी, जबकि संगठित अपराध में स्वतंत्र सबूत पहले से ही बहुत कम मिलते हैं। नतीजतन, आरोपी लोग बरी हो गए हैं, और पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है।

शिकायत दर्ज करने में देरी भी एक बड़ी समस्या रही है। पीड़ित या उनके अभिभावक अक्सर समाज के डर, परिवार की इज़्ज़त, पैसे की कमी और अपराधियों की धमकियों की वजह से लंबे समय तक चुप रहते हैं। इस देरी को कोर्ट शक की नज़र से देखते हैं, जिससे केस और कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा, घटनाओं का पूरा क्रम न बता पाना, खासकर जब क्राइम कई महीनों या सालों में हुआ हो, तो टेक्निकल वजहों से पीड़ित की गवाही को खारिज कर दिया जाता है।

इस बैकग्राउंड में, सुप्रीम कोर्ट का नाबालिगों को 'पीड़ित गवाह' मानने का निर्देश भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। यह निर्देश यह मानता है कि बच्चों की तस्करी के शिकार क्राइम में साथी नहीं हैं, बल्कि स्ट्रक्चरल शोषण के शिकार हैं। 'पीड़ित गवाह' का कॉन्सेप्ट गवाही को जांचने के पुराने स्टैंडर्ड को इंसानी सच्चाई के साथ मिलाता है और कोर्ट को याद दिलाता है कि दर्दनाक यादें पूरी तरह से लॉजिकल या सीधी नहीं होतीं।

इस न्यायिक तरीके के तहत, अब यह ज़रूरी नहीं है कि पीड़ित की गवाही हर बात पर पूरी तरह से एक जैसी और बिना गलती वाली हो। छोटी-मोटी उलझनें, घटनाओं के क्रम में साफ़ न होना, या डिटेल्स में अंतर को झूठ या मनगढ़ंत बातों के सबूत के तौर पर नहीं, बल्कि इंसानी रिएक्शन के तौर पर देखा जाता है। इससे प्रॉसिक्यूशन को हालात के सबूत और पीड़ित के बयान के मिले-जुले मूल्यांकन के आधार पर अपराध का एक बड़ा फ्रेमवर्क पेश करने में मदद मिलती है।

उत्तर भारत में जहरीली हवा का घेरा, क्या चीन के 'राष्ट्रीय आपातकाल' मॉडल से सुधरेगी भारत की सेहत?

उत्तर भारत एक बार फिर जहरीली हवा की गिरफ्त में है। लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। धूल और धुएं की परत जनस्वास्थ्य के लिए संकट बन चुकी है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक कब गंभीर श्रेणी में पहुंच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि, इस गंभीर होती समस्या से पार पाने के लिए दिल्ली सरकार ने 'ग्रैप' के प्रावधानों को लागू करने समेत कई उपाय आजमाए, मगर वे कारगर साबित नहीं हो सके।

पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीनपीस की एक रपट के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली दुनिया भर में तमाम देशों की राजधानियों में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। सवाल है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस संकट से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर को कोई स्थायी समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती? कागज पर भले ही सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे यहां व्यवस्था प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कितनी कारगर है।

इस मामले में अगर हमारे पड़ोसी देश चीन की बात की जाए, तो वह भी कभी खतरनाक प्रदूषण से जूझ रहा था, मगर एक दशक के भीतर ही वह अपनी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में कामयाब रहा। सबसे अहम सवाल यह है कि तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भारत दुनिया के दूसरे देशों से सबक क्यों नहीं ले रहा है। हालांकि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भारत ने कई उपाय किए हैं, लेकिन धीमी गति और जमीनी स्तर पर कमजोर प्रवर्तन की वजह से उनका प्रभाव सीमित ही रहा। वहीं, चीन ने प्रदूषण को राष्ट्रीय आपातकाल मानकर तेज गति से काम किया।

चीन की इस सफलता में निगरानी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। वहां एक व्यापक वायु निगरानी तंत्र बनाया गया, जो शहर-दर-शहर और यहां तक कि कारखानों से होने वाले प्रदूषण पर नियमित नजर रखता था। इससे उन्हें उत्सर्जन के स्रोतों का एक सटीक डेटा मिला और उसी के मुताबिक कार्रवाई की गई।

इसी के साथ चीन ने अपनी परिवहन प्रणाली में भी बदलाव किया। बेजिंग जैसे शहरों में मेट्रो नेटवर्क का

विस्तार किया गया, चौड़े पैदल यात्री क्षेत्र बनाए गए, निजी वाहन पर निर्भरता कम की गई और साथ ही सार्वजनिक परिवहन में निवेश किया गया। इसी के समांतर प्रदूषणकारी उद्योगों के प्रति भी चीन ने सख्ती दिखाई। ऐसे उद्योगों को स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ मोड़ कर कोयले पर निर्भरता को भी कम किया गया। गैस आधारित उपकरणों ने अनगिनत कोयला इकाइयों की जगह ली, जिस वजह से सल्फर उत्सर्जन में काफी कमी आई।

भारत की बात की जाए तो यहां अभी भी कोयले पर निर्भरता काफी ज्यादा है। जबकि चीन का उदाहरण दिखाता है कि मजबूत प्रवर्तन और एकीकृत सरकारी दृष्टिकोण से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रदूषण से आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होता है, लिहाजा तत्काल कुछ सार्थक और ठोस उपाय करने की जरूरत है।

देखा जाए तो आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारियां पर्यावरण प्रदूषण की वजह से ही हो रही हैं। मलेरिया, एड्स और तपेदिक से हर साल जितने लोगों की मौत होती है, उससे कहीं ज्यादा लोग प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण दम तोड़ देते हैं। बहरहाल, सवाल यही उठता है कि वायु प्रदूषण से हर साल होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दशकों से यह बात सरकार और समाज सबको मालूम है, इसके बावजूद सामूहिक प्रयासों को गति नहीं मिल पा रही है। ऐसा लगता है कि लोग अपने त्रासदीपूर्ण भविष्य को लेकर जरा भी चिंतित नहीं हैं। जबकि देश में वायु प्रदूषण की समस्या इतनी जटिल होती जा रही है कि भविष्य अंधकारमय प्रतीत हो रहा है।

दरअसल, आज मनुष्य भोगवादी जीवनशैली का इतना आदी और स्वार्थी हो गया है कि अपने जीवन के मूल आधार वायु को दूषित करने पर आमादा है। इस मामले में नैतिकता, धर्म, कर्तव्य सब पीछे छूट रहा है। भौतिकतावादी जीवनशैली और विकास की अंधी दौड़ में आज मनुष्य ये भी भूल गया है कि वायु प्रदूषण धीरे-धीरे कितना खतरनाक रूप धारण कर रहा है। बढ़ते वाहनों और कारखानों से निकलता धुआं, वृक्षों की कटाई और मनुष्य द्वारा फैलाई जा रही गंदगी हवा-पानी को इस कदर प्रदूषित कर रही हैं कि इससे बीमारियां भी दोगुनी गति से फैल रही है।

मानवीय सोच और विचारधारा में इतना ज्यादा बदलाव आ गया है कि भविष्य की जैसे कोई चिंता ही नहीं है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि अपने कृत्यों के कारण आज मनुष्य प्रकृति को रिक्त करता चला जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण असंतुलन से भूमंडलीय ताप, अम्लीय वर्षा, हिमनदों का पिघलना, समुद्र का जल-स्तर बढ़ना, मैदानी नदियों का सूखना, उपजाऊ भूमि का घटना और रेगिस्तानों का दायरा बढ़ना जैसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं। ये सारा किया कराया मनुष्य का है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके घातक प्रभाव को झेलने के बावजूद हम अब भी नहीं चेत रहे हैं।

साल-दर-साल भारत में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, या फिर हमारा समाज, कोई भी प्रदूषण से लड़ने के लिए गंभीर नजर नहीं आता है। अब समय आ गया है कि प्रदूषण से पार पाने के लिए सरकारी स्तर पर दीर्घकालीन नीतियां बनाई जाएं और उन्हें धरातल पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। साथ ही लोगों को अपने स्तर पर वे सभी जतन करने की जरूरत है, जो हवा को जहरीली होने से रोकें।

अब तक जो भी प्रयास हुए हैं, वे वायु प्रदूषण से निपटने में कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी बड़ी और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हमें विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में किए जा रहे उपायों से सीख लेने की जरूरत है। वायु प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है और इसे आपसी सहमति एवं ईमानदार प्रयास के बिना हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए तात्कालिक कार्रवाई के बजाय निरंतर प्रयासों की जरूरत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना, वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना जैसे उपाय दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं। पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए किसानों को बेहतर तकनीक और प्रोत्साहन प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे अधिक पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाएं। इसके साथ ही निर्माण स्थलों पर प्रदूषण-नियंत्रण उपायों का सख्ती से पालन और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता है। एक व्यवस्थित निगरानी तंत्र से पूरे वर्ष वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करना जरूरी है, ताकि प्रदूषण के स्तर को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। वास्तव में यह वक्त सिर्फ सोचने और चिंता करने का नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर कुछ ठोस उपाय करने का है।

रील वाली रफ्तार में कहीं छूट न जाए असली जिंदगी, स्क्रीन के पीछे का संघर्ष भी पहचानिए

कुछ समय से ऐसा प्रतीत होता है, मानो हर साल पिछले साल से कुछ अधिक तेज रफ्तार से गुजर रहा है। एक तरह की भ्रामक स्थिति कभी-कभी मन में निर्मित होने लगती है कि जो रफ्तार और व्यस्तता हम महसूस कर रहे हैं, वास्तव में भी क्या जीवन इतनी ही गति से आगे बढ़ रहा है। यह तो निश्चित है कि इस साल के हर महीने हम सब बहुत व्यस्त बने रहे। भले ही हम अपनी व्यावसायिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हों, पर इसके अतिरिक्त भी हमारे आसपास कोई न कोई महत्त्वपूर्ण विषय भी लगातार चर्चा में बना रहा। शायद हम सबने यह महसूस किया होगा कि खबरों और मुद्दों की रफ्तार इस बार पहले से अधिक तेज बनी रही। एक विषय आता, उतनी ही जल्दी वह गुजर जाता और उसकी जगह कोई नया विषय ले लेता।

जब कुछ नया विषय हमें नहीं मिलता, तब हमारे पास अलग-अलग मनोरंजन के साधन बने रहे। हम सेकंडों और मिनटों के रील में उलझे रहे, तो कभी खुद के चित्रों को हमारे नए साथी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआइ के जरिए अलग-अलग तेवर देते रहे। कुछ न कुछ अनोखा आजमाते रहे, जिसे हम चाह कर भी सीखना नहीं कह सकते, क्योंकि सीखने का मकसद व्यापक अर्थ लिए होता है। यह सब केवल सुगम मनोरंजन की श्रेणी में ही रहा।

कम अवधि में बड़ा मजा इस साल का सबसे बड़ा आकर्षण हम सब के लिए रहा। जहां फिल्मों में जीवन से प्रेरित कहानियों को लगभग तीन घंटे में प्रस्तुत किया जाता रहा है, हमने अपने वास्तविक जीवन के किसी सामान्य से दिन को कुछ मिनटों और सेकंडों में ही बांट दिया है। यही हमारी एकाग्रता की अवधि का सर्वोच्च समय बन गया है।

थोड़ी-सी जानकारी से ही हम सब कुछ सीख-समझ लेते हैं और कुछ मिनट में ही प्रसारित भी कर देते हैं। हम गंभीर मुद्दों पर भी त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो गए हैं, क्योंकि हम आनलाइन माध्यम पर बहुत से प्रभावशाली या नामी-गिरामी हस्तियों का लिखा पढ़ते रहते हैं और हमें सब जानकारी मिल जाती है। खबरों की हम

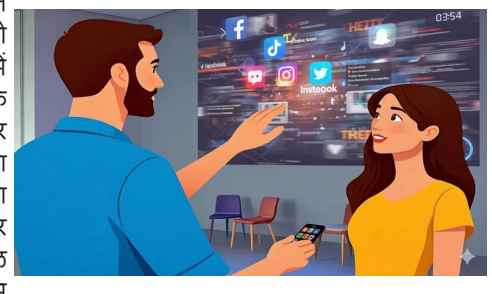

तक पहुंचने की रफ्तार बहुत अधिक है, इसलिए खुद से सोचने-समझने का समय अब हमारे पास बचता ही नहीं है।

हम केवल मूकदर्शक से बने हुए हैं, जो बिना थमे सब कुछ ग्रहण किए जा रहे हैं। यह सोचना जरूरी है कि ये दौड़ते पहिए इस जीवन पर किसने कस दिए हैं। क्या हम वास्तविकता देख रहे हैं? क्या सकारात्मक बदलाव की लहर भी उतनी ही रफ्तार से जीवन में और दुनिया में खुशियां फैला रही है? या हम सब केवल आभासी दुनिया में ही व्यस्त बने हुए हैं? जो कुछ हो रहा है, वह स्क्रीन के उस तरफ है और हमारी आंखों के ठीक सामने।

जरूरत है कि स्क्रीन को हटाकर हम अपने आसपास खुली आंखों से जीवन को देखें। देश और दुनिया की वास्तविकता का खुद के विवेक से अवलोकन करें। फटाफट भागते युग में पलक झपकते ही कोई एक देश से दूसरे देश पहुंच जाता है, तो हमें लगता है दुनिया तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, पर किसी के रोज की भोजन थाली में रोटी और चटनी के साथ सब्जी को जोड़ने में उसे कई साल लग जाते हैं।

बदलाव की रफ्तार, उसकी चाल, दिशा और मकसद को समझना पेचीदा है। कुछ बदलाव पल भर में आ जाते हैं, कुछ को पूरा जीवन लग जाता है और उसके बाद भी जरूरी बदलाव नहीं आ पाते। कार चलाते व्यक्ति का हवाईजहाज में बैठने का सफर संभव है, कुछ वर्षों में तय हो जाए, पर पैदल चलते मुसाफिर को सामान्य सुरक्षित परिवहन तक मिलना भी मुश्किल हो सकता है।

जब संपन्न परिवार के बच्चों के लिए विदेश में पढ़ाई करना सामान्य होता जा रहा है, तो हमें लगने लगता है, आज का समय कितनी संभावनाएं लिए हुए है। वहीं किसी मजदूर ने वर्षों तक रुपए जुटा कर अपने बच्चे को शिक्षित किया है, पर अब बच्चा नौकरी के लंबे इंतजार में है, उनका समय वहीं रुक-सा जाता है। अपनी ही तरह अपने बच्चे को मजदूर न बनाने का दृढ़ इरादा, मेहनत के अनुसार पारिश्रमिक और सम्मान न मिल पाने की हताशा से उपजा निर्णय है, जो आगे बढ़ने के सारे दरवाजे किसी के लिए बंद कर देता है।

इस तरह का संघर्ष बरसों से एक-सा बना हुआ है। अगर वास्तव में इस रफ्तार से समय बेहतर हो रहा है, तो यकीनन मूलभूत सुविधाएं सबकी पहुंच में हो रही होंगी। अगर हमारा समाज शिक्षित और सभ्य बन रहा है, तो हमारे विषय अब पहले से अलग होंगे, हमारा शब्दकोश शिष्टाचार के शब्दों से भरा हुआ होगा, हमारे भीतर उदारता और सहिष्णुता होगी। हम सब अब सुरक्षित और भविष्य को लेकर निश्चिंत महसूस करते होंगे।

यह जीवन चकाचौंध रोशनी से कभी नहीं भर सकता। उसमें तो ठीक से देखना भी मुश्किल होता है। हम कितनी देर तक देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन से बिखरती रंग-बिरंगी चमकीली रोशनी को? हमें मद्धिम रोशनी की जरूरत है, जिसमें धीरे-धीरे स्वाभाविक रूप से चीजें बदलती हुई स्पष्ट नजर आएं।

प्रगति होती है, तो मुस्कुराहट हमारे आसपास ही खिलती नजर आती है। छोटे-छोटे ईमानदार प्रयास धीरे-धीरे शक्ल लेते हैं। हमें अपनी इंद्रियों पर विश्वास करके खुद देखना और महसूस करना चाहिए। भले ही हमें सब कुछ तेज गति में देखने की आदत-सी हो गई है, पर वास्तविकता ठहराव की मांग करती है।

अपने मोबाइल, लैपटाप की स्क्रीन को कोने में रखकर हम एक बार खुद पर और अपने आसपास पर गौर कर सकते हैं। आम आदमी आज भी मेहनत कर अपना संघर्ष से भरा रास्ता तय कर रहा है, जहां आज भी उसकी यात्रा बहुत लंबी और मद्धिम बनी हुई है। गैरजरूरी व्यस्तताओं से खुद को मुक्त कर आज के समय की इस रफ्तार की लगाम को पकड़, इसे सही दिशा देना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है।

देश और समाज को जगाने वालों पर सवाल क्यों?

डॉ. सत्यवान सौरभ

किसी भी ज़िंदादिल समाज की पहचान यह नहीं है कि वह कितने रीति-रिवाजों को मानता है, बल्कि यह है कि वह उन रीति-रिवाजों को कितनी समझदारी से देखता है। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने सवाल पूछने वालों का सम्मान किया, वे आगे बढ़े; जबकि जिन्होंने उन्हें दबाने की कोशिश की, वे ठहराव और गिरावट का शिकार हो गए। आज, जब कोई व्यक्ति, संगठन या विचारक अंधविश्वास, पाखंड और झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसके इरादों पर सवाल उठाए जाते हैं। उसे धर्म-विरोधी, संस्कृति-विरोधी या समाज-विरोधी बताने की कोशिश की जाती है। यह ट्रेंड अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करता है– समाज को जगाने वालों पर सवाल क्यों?

आस्था और अंधविश्वास के बीच का अंतर समझना आज सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। आस्था इंसान को अंदर से मज़बूत करती है, नैतिकता, दया और आत्मविश्वास देती है। इसके उलट, अंधविश्वास डर, अज्ञानता और लाचारी पैदा करता है। जहाँ आस्था के साथ समझदारी होती है, वहीं अंधविश्वास समझदारी को कुचल देता है। बदकिस्मती से, आज सवाल पूछने वालों को चुप कराने और पाखंड के धंधे को बचाने के लिए जानबूझकर दोनों को मिलाया जा रहा है।

धर्म का असली मकसद कभी भी इंसानियत को अनजान रखना नहीं रहा है। भारतीय सोच में सवाल करने और बातचीत करने की परंपरा रही है। उपनिषदों से लेकर बुद्ध और कबीर तक, हर सोच ने जिज्ञासा और तर्क को अहमियत दी है। 'सवाल मत पूछो' का कल्चर भारतीय सोच की भावना के खिलाफ है। फिर भी, आज यह सोच बनाई जा रही है कि सवाल करना आस्था पर हमला है। यह न सिर्फ दिमागी तौर पर गलत है बल्कि सामाजिक तौर पर भी खतरनाक है। अंधविश्वास का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह शोषण को सही ठहराता है। लोगों को चमत्कार के नाम पर धोखा दिया जाता है, बीमारों को इलाज के बजाय जादूगरों के पास भेज दिया जाता है, और महिलाओं और बच्चों को डर और अपराधबोध में जीने के लिए मजबूर किया जाता है। जब कोई इन बुरी आदतों के खिलाफ बोलता है, तो उसे 'परंपरा तोड़ने वाला' कह दिया जाता है। असल में, वे खुद परंपरा को नहीं, बल्कि परंपरा के नाम पर होने वाले शोषण को चुनौती दे रहे हैं।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अंधविश्वास सिर्फ़ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है; इसका सीधा असर डेमोक्रेसी पर पड़ता है। जिस समाज में लॉजिक और साइंटिफिक सोच की कमी होती है, वह आसानी से अफवाहों, नफ़रत और झूठे प्रोपेगैंडा का शिकार हो जाता है। डेमोक्रेसी की नींव ही जानकार और समझदार नागरिकों पर टिकी होती है। जब नागरिक डर और अज्ञानता के आधार पर फ़ैसले लेने लगते हैं, तो डेमोक्रेटिक संस्थाएँ कमज़ोर होने लगती हैं।

भारत का संविधान इस बारे में साफ़ गाइडेंस देता है। यह सिर्फ़ गवर्नेंस का सिस्टम ही नहीं, बल्कि एक सोशल डॉक्यूमेंट भी है। संविधान साइंटिफिक सोच, बराबरी और इंसानी इज़्ज़त को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 51 नागरिकों की बुनियादी ज़िम्मेदारियों में साइंटिफिक सोच, इंसानियत और सुधार की भावना को शामिल करता है। इस नज़रिए से, अंधविश्वास के खिलाफ़ आवाज़ उठाना कोई पर्सनल सनक नहीं, बल्कि एक संवैधानिक ज़िम्मेदारी है।

इसके बावजूद, समाज को जगाने वालों को शक की नज़र से देखा जाता है। इसका एक कारण यह है कि बदलाव हमेशा असहज होता है। जो लोग लंबे समय से चले आ रहे सिस्टम से फ़ायदा उठाते हैं, वे बदलाव से डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर लोग सवाल करने लगे, तो उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। इसलिए, वे सवाल उठाने वालों को बदनाम करने का आसान रास्ता अपनाते हैं।

इस बहस में मीडिया और सोशल मीडिया का रोल भी बहुत ज़रूरी है। कुछ प्लेटफॉर्म जहां तर्क और लॉजिक को बढ़ावा देते हैं, वहीं सनसनी और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला कंटेंट भी तेज़ी से फैलता है। चमत्कारों की कहानियां, बिना साइंटिफिक दावे और डर फैलाने वाले मैसेज ज़्यादा वायरल होते हैं। ऐसे माहौल में, तर्क की आवाज़ अक्सर दबा दी जाती है, और तर्क देने वाले को 'नेगेटिव' या 'कॉन्ट्रोवर्शियल' करार दिया जाता है। इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ में एजुकेशन है। अगर एजुकेशन सिर्फ़ डिग्री पाने का ज़रिया बन जाए और उसमें साइंटिफिक सोच, सवाल करने की आदत और नैतिक हिम्मत की कमी हो, तो समाज में अंधविश्वास फैलना स्वाभाविक है। बच्चों को छोटी उम्र से ही यह सिखाया जाना चाहिए कि उन्हें बिना समझे हर बात मानने की ज़रूरत नहीं है। इज़्ज़त से असहमति और लॉजिकल सोच एक हेल्दी समाज की नींव हैं।

यह भी सच है कि हर बदलाव धीरे-धीरे आता है। समाज को जगाने वालों का रास्ता आसान नहीं होता। उन्हें विरोध, मज़ाक और कभी-कभी हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन पूरे इतिहास में, इन्हीं लोगों ने समाज को बनाया है। जब राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। जब डॉ. अंबेडकर ने जाति के भेदभाव को चुनौती दी, तो उन्हें भी सवालों का सामना करना पड़ा। आज, इन सभी समाज सुधारकों को सम्मान के साथ याद किया जाता है। आज के समय में ऐसी ही हिम्मत की ज़रूरत है। अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होने का मतलब किसी एक धर्म, वर्ग या समुदाय के लिए खड़ा होना नहीं है। यह इंसानी इज़्ज़त और ज़मीर के लिए खड़े होने के बारे में है। यह कहना कि धर्म में झूठ, पाखंड और डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, किसी के विश्वास का अपमान करना नहीं है, बल्कि उसकी रक्षा करना है।

ामाज को यह तय करना होगा कि वह किस रास्ते पर जाना चाहता है - डर और अज्ञानता की ओर या ज्ञान और प्रगति की ओर। अगर हम सच में एक मज़बूत, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक भारत चाहते हैं, तो हमें उन आवाज़ों को सुनना होगा जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। सवालों से डरने के बजाय, हमें उनका सामना करना चाहिए।

आखिर में, सवाल यह है कि समाज को जगाने वालों पर सवाल क्यों उठाया जाता है? शायद इसलिए कि एक जागा हुआ समाज सत्ता, पाखंड और शोषण से असहज महसूस करता है। लेकिन यही बेचैनी भविष्य की नींव भी है। अगर हम आज अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ खड़े होते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को एक ज़्यादा जागरूक, आज़ाद और मानवीय समाज विरासत में मिलेगा।

अंधविश्वास का अंत किसी एक आंदोलन से नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना से होगा। यह चेतना सवाल पूछने से शुरू होती है। इसलिए, जो लोग सवाल पूछते हैं और सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, वे समाज के दुश्मन नहीं, बल्कि उसके सच्चे दोस्त हैं।

22 लाख के गांजे के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

एडिशनल एसपी ने प्रेस कांफ्रेंस कर किया खुलासा

भदोही। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चौरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 कुंतल 880 ग्राम नाजायज गांजा, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 22 लाख रुपये बताई जा रही है, बरामद किया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त एक कार और चार फर्जी नंबर प्लेट भी जब्त की गई हैं।

इस पूरे मामले का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक भदोही शुभम अग्रवाल ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान किया। एएसपी ने बताया कि राजीव कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी भदोही के नेतृत्व में थाना चौरी पुलिस टीम द्वारा मिर्जामुराद-भदोही मार्ग पर अठगोड़वा पुलिया के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन को रोका गया। तलाशी लेने पर कार के भीतर छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रसान्त पटेल पुत्र जयप्रकाश पटेल, निवासी अमवा कला (भवानीपुर मजरा), थाना चौरी, उम्र 29 वर्ष तथा अनुराग पटेल पुत्र राजाराम पटेल, निवासी पचपटिया, थाना चौरी, उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 202/2025 धारा 318(4)/319(2) बीएनएस एवं 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे उड़ीसा से गांजा लाकर वाराणसी होते हुए भदोही ले जा रहे थे। गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका भी सामने आई है, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस के अनुसार वाहन में नंबर प्लेट बदल-बदल कर तस्करी की जाती थी ताकि पहचान से बचा जा सके।

एडिशनल एसपी ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जनपद में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस कार्रवाई में चौरी थाना पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम की अहम भूमिका रही।

एकमा की ओर से कम्बल वितरित कर की गई गरीबों, असहायों व बुनकरों की मदद

भदोही। अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ एकमा के तत्वावधान में शनिवार को गरीबों, असहायों व कालीन बुनकरों को कंबल वितरित किया गया।

नगर के मर्यादपट्टी में स्थित एकमा के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में कंबल बांटे गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने गरीबों, असहायों व कालीन बुनकरों को कंबल वितरित किए जाने पर एकमा के पदाधिकारियों की सराहना की। साथ ही उनके द्वारा गरीबों के शिक्षा पर भी जोर दिया गया। एकमा के अध्यक्ष मो. रजा खान और मानद सचिव पीयूष बरनवाल ने बताया कि लगभग 1500 लोगों में कंबल का वितरण किया गया। भीड़ अधिक होने के कारण कोतवाल सच्चिदानंद पांडेय पुलिस बल के साथ अंत तक वहां पर मौजूद रह कर भीड़ को नियंत्रित कर रहे थें। एसडीएम अरुण गिरी, क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार मिश्रा भी भीड़ नियंत्रित करते

हुए कंबल वितरण में सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर एकमा अध्यक्ष मो.रजा खां, पीयूष बरनवाल, शाहिद अंसारी, अमित मौर्या, आलोक बरनवाल सभासद अरविंद मौर्य आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहें।

मायूस हुए बच्चे

अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ एकमा में कम्बल वितरण की सूचना पर पहुंचे बच्चों के हाथों में कम्बल की जगह मायूसी हाथ लगी। कड़कड़ाती ठंड में समय 11 बजे कंबल वितरण की सूचना पर सुबह से ही 6 साल से 12 साल तक के बच्चे भी एक्मा भवन में पहुंच गए थे, लेकिन जब लगभग 12 बजे कंबल वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ तो उन्हें कम्बल नहीं दिया गया उन्हें खाली हाथ मायूस हो कर लौटना पड़ा।

मतेथू के प्राचीन हनुमान मंदिर का कायाकल्प, श्रद्धालुओं में खुशी

भदोही। सुरियावां कोतवाली क्षेत्र के मतेथू गांव स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में नई रेलिंग लगने से मंदिर की सुरक्षा और सुंदरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह कार्य गांव के उद्यमी महेश कुमार दुबे ने अपने निजी खर्च से कराया, जिसे लेकर ग्रामीणों व श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। रेलिंग लगने से अब मंदिर परिसर में आवारा पशुओं का प्रवेश रुकेगा और श्रद्धालु निश्चिंत होकर दर्शन-पूजन कर सकेंगे। इस सेवा कार्य की ग्रामीणों ने मुक्तकंठ से सराहना करते हुए इसे आस्था और सामाजिक जिम्मेदारी का सराहनीय उदाहरण बताया।

अटल बिहारी वाजपेई जन्म शताब्दी समारोह वर्ष 24/ 25 विधानसभा भदोही ब्लाक सभागार सुरियावा संपन्न

भदोही/ सुरियावा। शनिवार को अटल स्मृति सम्मेलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खादी ग्रामोंउद्योग आयोग के सदस्य नागेंद्र रघुवंशी उपस्थित रहे इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा संचालन जिला उपाध्यक्ष अखंड प्रताप ने किया इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अटल बिहारी वाजपेई भारत रत्न के जीवन पर आधारित तमाम विषयों की चर्चा की अटल बिहारी वाजपेई विराट व्यक्तित्व और मर्म को महसूस कर नापतोल कर शब्द रखने वाले वाक पटु हमारे परम स्नेही हमारे गौरव के प्रतीक प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई को हम सभी भारतवासियों की ओर से उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं ऐसे तमाम विषयों पर खुलासा करते हुए मुख्य अतिथि ने प्रकाश डाला संगठन से सत्ता तक यह भाषण केवल शब्दों का कम नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की उस यात्रा का स्मरण है जहां सत्ता का शिकार संगठन की सीढ़िया से चढ़कर प्राप्त किया गया यह कथा है अटल बिहारी वाजपेई की एक ऐसे राजनेता की जिनकी राजनीतिक यात्रा व्यक्ति से पहले विचार के पद से पहले संगठन की सत्ता से पहले संघर्ष की कहानी है अध्यक्षता कर रहे दीपक मिश्रा

ने अपने विचार को रखते हुए कहा अटल बिहारी वाजपेई भारतीय राजनीति में उस पीढ़ी को प्रतिनिधि थे जिसने सत्ता को लक्ष्य नहीं साधन माना उनकी यात्रा किसी राजवंश की देन नहीं थी नहीं किसी आकस्मिक जन लहर का परिणाम था यह यात्रा संघ की शाखाओं में अनुशासन सीखने से आरंभ होती है जनसंघ की बैठकों में विचार करने से आगे बढ़ती है और अंततः लोकतांत्रिक सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचती है 1940 के दशक में जब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता था उसी काल में अटल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे संघ उनके लिए केवल संगठन नहीं था बल्कि जीवन दृष्टि था राष्ट्र सर्वोपरि व्यक्ति साधन है 1957 का लोकसभा चुनाव अटल की राजनीतिक यात्रा का निर्णायक मोड़ था बलरामपुर से निर्वाचित होकर वह संसद पहुंचे उस संसद में जहां जवाहरलाल नेहरू जैसे वैश्विक नेता उपस्थित थे 1967 में जनसंख्या की राजनीतिक स्वीकारता बढी अटल पहली बार सरकार के निकट पहुंचे 1977 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार बनी 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1984 में मात्र दो सिटे किंतु अटल बिहारी वाजपेई ने उस समय सत्ता की शॉर्टकट राजनीति नहीं चुनी 1996 में अटल पहली बार प्रधानमंत्री बने 13 दिन की सरकार रही और पराजय नहीं थी वह सिद्धांत की विजय थी 1998 में पुनः प्रधानमंत्री बने भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर आत्मनिर्भर सुरक्षा नीति की घोषणा की 1999 में कारगिल युद्ध के समय उनके नेतृत्व स्पष्ट करता है ऐसे तमाम विषयों को समाहित करते हुए अटल के स्मृति पर चर्चा की गई और उन्हें याद किया गया और उन्हें सच्ची श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी जिला प्रवासी पूर्व जिला अध्यक्ष जौनपुर रामविलास पाल जिला उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा सुरेंद्रनाथ पांडेय गोवर्धन राय जिला मीडिया प्रभारी भाजपा अखंड प्रताप सिंह राजेंद्र दुबे नितेश त्रिपाठी मंडल अध्यक्ष संजय सरोज राकेश गुप्ता अशोक पाठक स्वरूप बिद नागेन्जय सुरेश पासी चंद्रशेखरसिंह सम्मानित सभी मातृशक्ति रेशमा बानो रीना श्रीवास्तव सीमा द्विवेदी दीपक पाठक युवा नेता मनीष पांडेय शिवम तिवारी अखिलेश तिवारी दीपक सिंह तथा सम्मानित सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सुंदरकांड का भव्य आयोजन संपन्न

भक्ति-संगीत से सराबोर हुआ हनुमत विला परिसर

फाफामऊ। फाफामऊ क्षेत्र के मलाका महरूडीह गांव स्थित रामू भैया पांडे के आवास हनुमत विला में शनिवार को संगीतमय सुंदरकांड का भव्य आयोजन श्रद्धा, भक्ति और उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आयोजन के दौरान सुंदरकांड पाठ के साथ प्रस्तुत किए गए सुमधुर भजनों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया।

सुंदरकांड पाठ के समय श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम और संकटमोचन हनुमान के जयकारों के साथ पूरे उत्साह से सहभागिता निभाई। भक्ति संगीत और सामूहिक पाठ ने उपस्थित भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति से भर दिया।

इस पावन अवसर पर प्रमुख रूप से रमेश नारायण मिश्रा, रमेंद्र नारायण त्रिपाठी, रामू भैया पांडे, श्यामू भैया पांडे, सोनू पांडे, नागेश त्रिपाठी, सुधीर शुक्ला, रमेश कुमार शुक्ला, लकी मिश्रा, दीपक मिश्रा, धीरज मिश्रा, रत्नेश सिंह, रवि मौर्य, सुधाकर पांडे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

सुंदरकांड पाठ के उपरांत विधिवत आरती संपन्न हुई तथा सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस संगीतमय सुंदरकांड आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करना है।

कार्यक्रम के सफल आयोजन पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने आयोजकों के प्रयासों की सराहना करते हुए ऐसे धार्मिक आयोजनों को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया।

भदोही में शिक्षक निर्वाचन की अनंतिम मतदाता सूची पर सवाल

हजारों अंशकालिक व कथित फर्जी मतदाताओं के शामिल होने का आरोप

भदोही। विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (वाराणसी खंड) की अनंतिम मतदाता सूची को लेकर जनपद भदोही में गंभीर आपत्तियां सामने आई हैं। शिक्षक नेता सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि अनंतिम मतदाता सूची में नियमों के विपरीत हजारों अंशकालिक शिक्षकों, गैर-शिक्षकों एवं कथित फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल कर दिए गए हैं, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

श्री त्रिपाठी ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ, मंडलायुक्त वाराणसी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को पत्र भेजकर आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही ई-मेल के माध्यम से भी शिकायत प्रेषित की गई है।

उन्होंने बताया कि 02 दिसंबर को प्रकाशित अनंतिम मतदाता सूची में पहले विद्यालयों के नाम अंकित नहीं थे। शिकायत के बाद 05 दिसंबर को विद्यालयों के नाम सहित संशोधित सूची जारी की गई, लेकिन उसमें भी अनेक गंभीर त्रुटियां पाई गईं। भदोही की निर्वाचक नामावली के पार्ट संख्या 23 व 26 में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों, मदरसा प्राइमरी शिक्षकों तथा ऐसे लोगों को भी मतदाता बना दिया गया है, जिनके विद्यालयों का नाम स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है।

शिक्षक नेता का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग के 05 सितंबर 2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार अंशकालिक शिक्षक विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदाता होने के पात्र नहीं हैं। इसके बावजूद जनपद भदोही के सैकड़ों वित्तविहीन विद्यालयों के हजारों अंशकालिक शिक्षकों को मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है, जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण पत्र व शैक्षिक प्रमाण पत्रों की समुचित जांच किए बिना ही आवेदन पत्रों का सत्यापन कर दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ गैर-शिक्षकों के आवेदन पत्र भी सत्यापित कर उन्हें मतदाता बना दिया गया है।

श्री त्रिपाठी ने कहा कि एक ओर जहां शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के कई वास्तविक शिक्षक मतदाता सूची से बाहर हैं, वहीं दूसरी ओर निजी विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षक और कथित फर्जी मतदाता बड़ी संख्या में सूची में शामिल कर दिए गए हैं।

उन्होंने मांग की है कि पूरी अनंतिम मतदाता सूची को निरस्त किया जाए और केवल वास्तविक व पूर्णकालिक शिक्षकों को ही मतदाता सूची में शामिल किया जाए। साथ ही जिन अधिकारियों द्वारा फर्जी या अवैध मतदाताओं का सत्यापन किया गया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए।

मंदिर परिसर में चोरी की घटना से बढ़ी सुरक्षा की चिंता, स्थायी पुलिस चौकी की उठी मांग

भदोही।जनपद के सुंदरबन, कटेबना स्थित श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर (ट्रस्ट) परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। गुरुवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने मंदिर क्षेत्र में खड़े ट्रक से लगभग 40 हजार रुपये मूल्य की दो बैटरियां चोरी कर लीं। घटना की सूचना तत्काल ज्ञानपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

मंदिर की पीठाधीश्वर माँ राजलक्ष्मी मंदा जी ने कहा कि मंदिर क्षेत्र चारों ओर से वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिससे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। उन्होंने मांग की कि मंदिर परिसर में स्थायी पुलिस चौकी स्थापित की जाए, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, अवैध वन कटान पर रोक तथा मंदिर में निवासरत पीठाधीश्वर व सेवादारों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

स्थानीय नागरिकों का भी कहना है कि यह क्षेत्र एक बड़ा धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। ऐसे में यहां सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था न केवल श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक है, बल्कि इससे क्षेत्र में विकास और जनविश्वास को भी मजबूती मिलेगी।

बगहा मोड़ पर एक भीषण सड़क हादसा

प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बगहा मोड़ पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से अपाचे बाइक पर सवार एक युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अपाचे बाइक पर सवार दोनों लोग वाराणसी से प्रयागराज की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बगहा मोड़ के पास तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में युवती ट्रक के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, वहीं अपाचे चालक दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही हंडिया पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटनाग्रस्त अपाचे बाइक का नंबर UP 66 AE 3598 बताया गया है। पुलिस द्वारा ट्रक चालक की तलाश की जा रही है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस हृदयविदारक हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।

पकरी तिराहा रेलवे क्रॉसिंग बनी जानलेवा, बंद फाटक के नीचे से गुजर रहे दोपहिया वाहन, बड़े हादसे की आशंका

भदोही।भदोही रेलवे स्टेशन के सबसे नजदीक स्थित पकरी तिराहा रेलवे क्रॉसिंग इन दिनों रेलवे विभाग की घोर लापरवाही का प्रतीक बन चुकी है। यहां की अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण प्रतिदिन हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। फाटक बंद होने के बावजूद उसकी असामान्य रूप से अधिक ऊँचाई होने के कारण दोपहिया वाहन चालक नियमों की अनदेखी करते हुए फाटक के नीचे से निकल जाते हैं, जबकि चारपहिया वाहन चालकों को मजबूरी में लंबा इंतज़ार करना पड़ता है।

स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थिति कोई एक-दो दिन की नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही समस्या है। ट्रेन के आवागमन के दौरान भी बाइक सवार जोखिम उठाकर क्रॉसिंग पार कर लेते हैं। यह दृश्य रोज़ का हो चुका है, जो कभी भी भीषण रेल दुर्घटना में बदल सकता है। विशेषकर सुबह और शाम के समय, जब यातायात का दबाव अधिक रहता है, तब हालात और भी भयावह हो जाते हैं।

पकरी तिराहा रेलवे क्रॉसिंग से प्रतिदिन स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग गुजरते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि रेलवे फाटक की डिजाइन ही सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं है। न तो फाटक के नीचे अतिरिक्त अवरोधक लगाए गए हैं और न ही कोई चेतावनी बोर्ड या निगरानी तंत्र मौजूद है, जो लोगों को नियमों के पालन के लिए बाध्य कर सके।

स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाया है कि यदि किसी दिन ट्रेन की चपेट में आकर कोई बाइक सवार या राहगीर घायल अथवा मृत हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा रेलवे प्रशासन या व्यवस्था की चुप्पी? लोगों का कहना है कि जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती, तब तक जिम्मेदार विभाग हरकत में नहीं आते, जो बेहद चिंताजनक है।

क्षेत्रवासियों और सामाजिक संगठनों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि फाटक की ऊँचाई को मानक के अनुरूप किया जाए, फाटक के नीचे से निकलने की संभावना को समाप्त करने के लिए ठोस अवरोधक लगाए जाएं, चेतावनी साइन बोर्ड, सायरन और लाइट सिस्टम को दुरुस्त किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की जाए।

लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो पकरी तिराहा रेलवे क्रॉसिंग पर यह लापरवाही किसी दिन निर्दोष लोगों की जान ले सकती है। अब क्षेत्रवासी रेलवे विभाग से केवल आश्वासन नहीं, बल्कि तत्काल और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

अखलाक केस क्यों बंद करना चाहती थी योगी सरकार? कोर्ट ने पलट दिया पूरा मामला

ग्रेटर नोएडा के अखलाक लिंचिंग केस में उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। सूरजपुर की जिला अदालत ने लिंचिंग आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने से जुड़ी योगी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। जो याचिका मुकदमा वापस लेने के लिए जारी की दायर की गई थी। उसे अदालत ने साफ कर दिया है कि यह मामला बंद नहीं होगा और आरोपियों के खिलाफ ट्रायल जारी रहेगा। यूपी सरकार की ओर से दाखिल की गई केस वापसी की अर्जी पर अदालत ने सुनवाई के बाद तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष यानी प्रोसीक्यूशन जो पक्ष है उसको उसकी दलीलों को आधारहीन और महत्वहीन यानी बेसलेस एंड इर्रेलेवेंट बताया। कहा कि केस वापस लेने के लिए कोई ठोस कानूनी वजह सामने नहीं रखी गई। इस फैसले के साथ ही यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की वो कोशिश जिसके जरिए अखलाक लिंचिंग के आरोपियों को राहत दिलाने की बात कही जा रही थी अब कानूनी तौर पर आगे नहीं बढ़ पाएगी। यह याचिका यूपी सरकार ने अक्टूबर 2025 में ट्रायल कोर्ट में दाखिल की थी। यह फैसला कानूनी और लोकतांत्रिक नजरिये, दोनों ही तरह से महत्वपूर्ण है। यह निर्णय बताता है कि न्याय व्यवस्था भावनाओं के हिसाब से नहीं चलती।

सितंबर 2015 में ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा में भीड़ ने अखलाक की इस शक में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी कि उसके घर में गोमांस है। मॉब लिंचिंग की इस वारदात ने तब पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में 18 अभियुक्तों पर अभी केस चल रहा है और फिलहाल सभी जमानत पर हैं। इस साल अक्टूबर में अचानक से यूपी सरकार ने केस वापस लेने का फैसला ले लिया।

सरकार का तर्क

यूपी सरकार ने हवाला देते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लेने और नियोजनको संयुक्त निदेशक के अनुमति मांगने के लिए अदालत में याचिका निर्देशों के बाद सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता (आपराधिक) द्वारा यह आवेदन दायर किया गया था। कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि अखलाक हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ेगा और मामले की नियमित सुनवाई होगी।

मॉब लिंचिंग में बेटा भी हुआ जख्मी, 19 पर था दर्ज हुआ था केस

28 सितंबर 2015 की रात प्रतिबंधित मांस को लेकर अफवाह फैली और भीड़ ने अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। अखलाक के बेटे दानिश (22) को भी गंभीर चोट लगी थी। पुलिस ने जांच के बाद कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया था। सभी पर हत्या, दंगा भड़काने और जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

अखलाक पक्ष के अधिवक्ता यूसुफ सैफी ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से लगाई गई याचिका को निरस्त कर दिया है। अभियोजन को आगे गवाहों के बयान दर्ज कराने को कहा गया है। अदालत ने पुलिस आयुक्त और डीसीपी को निर्देशित किया कि अगर जरूरत हो तो गवाहों को सुरक्षा दी जाए। इससे पहले इस केस में 12 और 18 दिसंबर को भी सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष के समय मांगने के कारण फैसला नहीं हो पाया था। सुनवाई के दौरान सीपीएम नेता नेता वृंदा करात भी कोर्ट पहुंची और कहा कि यह न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है।

137 भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्र

कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने बदला सियासी संतुलन!

सपा बनी भावी नगरसेवकों और मतदाताओं की पहली पसंद

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी । 137 भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आगामी भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल चरम पर है। कांग्रेस पार्टी के भीतर लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी और 18 नगरसेवकों की बगावत ने जहां पार्टी की नींव कमजोर कर दी है, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) ने इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर खुद को सबसे मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित कर लिया है। यह विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल होने के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहां की राजनीति हमेशा विकास, पहचान और बुनियादी सुविधाओं के इर्द-गिर्द घूमती रही है।

2019 से बदली भिवंडी पूर्व की सियासतः

कभी भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का नाम केवल औपचारिक उपस्थिति तक सीमित रह गया था। लेकिन वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। सपा उम्मीदवार रईस शेख ने शिवसेना के तत्कालीन विधायक रूपेश म्हात्रे को बेहद करीबी मुकाबले में पराजित कर सपा की खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस दिलाई।2019 के चुनाव में रईस शेख को 45,531 मत मिले, जबकि रूपेश म्हात्रे को 44,081 मतों पर संतोष करना पड़ा। महज 1,450 मतों के अंतर से मिली इस जीत ने भिवंडी पश्चिम की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत कर दी।

2024: विकास के नाम पर निर्णायक जनादेशः

वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में रईस शेख ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाया गया। इस बार मुकाबला भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट) के प्रत्याशी संतोष शेट्टी से था। चुनाव परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि जनता ने विकास के नाम पर भरोसा जताया। रईस शेख को 1,19,687 मत मिले, जबकि संतोष शेट्टी को 67,672 मत प्राप्त हुए.52,015 मतों की विशाल जीत ने सपा को इस क्षेत्र में निर्विवाद ताकत बना दिया।

सात साल का कार्यकाल और विकास की राजनीतिः

पिछले सात वर्षों में विधायक रईस शेख ने क्षेत्र में कई बुनियादी विकास कार्य कराए। पहाड़ी इलाकों में

जलापूर्ति सुधार, सड़क कांक्रीटीकरण, नालियों का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाओं में इजाफा, डिजिटल स्कूल, श्मशान भूमि, कबिस्तान और झोपड़पट्टी पुनर्विकास जैसे मुद्दों पर काम हुआ। इन्हीं कार्यों का परिणाम है कि आज सपा कार्यालय में टिकट मांगने वाले भावी नगरसेवकों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। कई पूर्व नगरसेवक और विभिन्न दलों से जुड़े नेता भी सपा की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं।

2017 का मनपा चुनाव और कांग्रेस की चूकः

वर्ष 2017 के महानगरपालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कुल साढ़े 12 प्रभागों में कांग्रेस ने 6 प्रभागों पर कब्जा जमाया था। समाजवादी पार्टी को केवल एक प्रभाग में 2 सीटें मिली थीं।

एक प्रभाग आरपीआई (एकतावादी) के पैनल ने जीता था, जबकि शिवसेना और भाजपा ने मिलकर चार प्रभागों में जीत दर्ज की थी। लेकिन यह बढ़त ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। ढाई साल बाद हुए महापौर चुनाव में कांग्रेस के इस क्षेत्र से जीते 13 नगरसेवकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी। इन बागी नगरसेवकों ने कोणार्क विकास आघाड़ी के उम्मीदवार को समर्थन देकर महापौर बना दिया। यहीं से कांग्रेस की साख और संगठन दोनों को गहरा झटका लगा।

मुस्लिम बहुल इलाकों में सपा की मजबूत पकड़ः

भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कुल 12 में से 8 प्रभाग मुस्लिम बहुल माने जाते हैं। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सेक्युलर राजनीति का गढ़ रहा है। वन विभाग की जमीन पर बसे झोपड़पट्टियों और अनधिकृत मकानों में रहने वाले मतदाता यहां चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।शांतिनगर, गायत्रीनगर, गैबीनगर, गुलजार नगर, मिल्लतनगर, नवी बस्ती जैसे इलाके मुस्लिम बाहुल्य हैं, जहां सपा को लगातार बढ़त मिलती रही है। वहीं कामतघर, ताडाली,टेमघर, भादवड़, शास्त्रीनगर, मानसरोवर,पद्मानगर, कणेरी और पोगांव जैसे क्षेत्र हिंदू बहुल हैं। यहां आगरी, कोली, तेलगू और उत्तर भारतीय समाज की मौजूदगी के कारण भाजपा और शिवसेना का प्रभाव बना रहता है।

वर्ष 2017 के चुनाव के परिणाम :

प्रभाग क्रमांक - 2 - कांग्रेस
प्रभाग क्रमांक - 3 - आरपीआई (A)
प्रभाग क्रमांक -4 - कांग्रेस
प्रभाग क्रमांक -9 - कांग्रेस
प्रभाग क्रमांक - 10 - कांग्रेस
प्रभाग क्रमांक - 11- सपा -2, कांग्रेस -2
प्रभाग क्रमांक -12- कांग्रेस
प्रभाग क्रमांक - 13- शिवसेना
प्रभाग क्रमांक - 14 - कांग्रेस
प्रभाग क्रमांक -15- शिवसेना
प्रभाग क्रमांक -16- भाजपा
प्रभाग क्रमांक - 17- भाजपा

2019 महापौर चुनाव में कांग्रेस के बागी नगरसेवक :

प्रभाग क्रमांक 2 अ,ब,क,ड - श्रीमति नमरा औरंगजेब अंसारी, श्रीमति मिसबाह इमरान खान, इमरान वली मोहम्मद खान और अहमद हुसैन सिद्दीकी।
प्रभाग क्रमांक -4 अ,ब,क
अरशद मोहम्मद असलम अंसारी, श्रीमति शबनम महबूब रहेमान अंसारी, श्रीमति अंजुम अहमद हुसैन सिद्दीकी।
प्रभाग क्रमांक -9 क,ड
श्रीमति राबिया मोहम्मद शमीम अंसारी, तफज्जुल हुसैन मकसूद हुसैन अंसारी।
प्रभाग क्रमांक-10 ब
श्रीमति शीफा अशफाक अंसारी।
प्रभाग क्रमांक -11 ड.
नसरूल्ला नूर मोहम्मद अंसारी।
प्रभाग क्रमांक 14 ब, ड.

बुनियादी समस्याएं बनी सबसे बड़ा मुद्दाः

भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र आज भी कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। अधिकांश इलाका पहाड़ी होने के कारण जलापूर्ति की समस्या स्थायी बनी हुई है। मोती कारखानों और डाइंग-साइजिंग उद्योगों के चलते प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मानसून के दौरान पहाड़ी खिसकने की घटनाओं का डर बना रहता है। कई इलाकों में सड़कें जर्जर हालत में हैं, साफ-सफाई व्यवस्था बेहद कमजोर है और सीवर लाइन की समस्या आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है।मुस्लिम बहुल इलाकों में विवाह समारोहों के लिए पर्याप्त शादी हॉल नहीं हैं, जिसके चलते लोगों को दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। संकरी गलियां और अनियोजित बस्तियां आपातकालीन सेवाओं के लिए भी चुनौती बनी हुई हैं।

श्रीमति हुस्ना परवीन मोहम्मद याकूब अंसारी, मतलूब अफजल खान।

कांग्रेस पार्टी के बागी नगरसेवकों को महाराष्ट्र शासन के नगर विकास विभाग ने विभागीय आयुक्त,कोकण भवन में तत्कालीन महापौर जावेद दलवी के दायर याचिका क्रमांक 1/2019 के सुनवाई निर्णय में मुख्यमंत्री के आदेशानुसार चुनाव लड़ने के लिए 6 साल तक बैन लगा दिया है।

भिवंडी में केबल नेटवर्क विवाद चली तलवार , छह के खिलाफ मामला दर्ज

भिवंडी। भिवंडी के कोपर क्षेत्र में केबल नेटवर्क के विवाद को लेकर एक युवक पर तलवार व रॉड से जानलेवा हमला किया गया। इस संबंध में नारपोली पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता राकेश भरत पाटील (उम्र 38 वर्ष), जो केबल नेटवर्क व्यवसाय से जुड़े हैं, 23 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 2.30 बजे श्री अरिहंत कंपाउंड, बिल्डिंग नंबर-जे, कोपर (भिवंडी) में मौजूद था। इसी दौरान केशव पाटील और उनके साथियों ने पुरानी रंजिश और केबल वायर काटने के विवाद को लेकर शिकायतकर्ता को धमकाया।

आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने हाथापाई करते हुए चप्पलों, मुक्कों और लातों से मारपीट की।शिकायत में बताया गया है कि यश पाटील ने तलवार से हमला कर शिकायतकर्ता के दाहिने हाथ की उंगली पर वार किया, जबकि अन्य आरोपियों ने लोखंडी रॉड से हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर हमला कर घायल कर दिया। हमले में शिकायतकर्ता को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।इस मामले में पुलिस ने केशव शिवराम पाटील (48), यश केशव पाटील (22), हर्ष केशव पाटील (28), अभिजीत शशिकांत पाटील (32), रोहित शरद पाटील (32) और समकांत म्हात्रे (42) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी कोपर क्षेत्र के निवासी हैं।

भिवंडी में नौकरी व हेवी डिपॉजिट पर घर दिलाने के नाम पर ठगी, होटल में बुलाकर 3.20 लाख रुपये ऐंठे

भिवंडी। भिवंडी शहर में नौकरी दिलाने व हेवी डिपॉजिट पर घर दिलाने के नाम पर 3.20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में भोईवाड़ा पुलिस थाने में दो आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है।

भोईवाड़ा पुलिस के अनुसार भिवंडी के नारपोली इलाके में रहने वाले अजीम अहमद जमाल अहमद सिद्दीकी (36) को रोजगार की तलाश थी। इसी दौरान उसे असारी कलीम रईस अहमद और करण रामप्रकाश गुप्ता ने उन्हें हेवी सिक्योरिटी डिपॉजिट पर फ्लैट दिलाने और उसमें काम उपलब्ध कराने का झांसा दिया।आरोप है कि अगस्त 2024 में आरोपियों ने शिकायतकर्ता को भिवंडी में साहिल होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहां आरोपियों ने बताया कि करण गुप्ता के नाम पर अल हारून अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 401 उपलब्ध है और उसे हेवी सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दिया जाएगा। इस बात पर भरोसा कर शिकायतकर्ता ने 3 लाख 20 हजार रुपये आरोपियों को दे दिए।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने इसी तरह 4 से 5 अन्य लोगों को भी फ्लैट और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा है। पैसे लेने के बाद न तो फ्लैट दिया गया और न ही कोई काम उपलब्ध कराया गया। जब शिकायतकर्ता ने रकम वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगे।जिसके बाद उसने थक हार कर भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कराया है।जिनकी तलाश में पुलिस सरगर्मी से जुट गई है।

भिवंडी में रात में सड़क की अवैध खुदाई की शोरगुल से जनजीवन प्रभावित, ठेकेदार पर मामला दर्ज

भिवंडी।भिवंडी शहर में नियमों की अनदेखी कर सार्वजनिक सड़क पर खुदाई कर नागरिकों की शांति भंग करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में भिवंडी शहर पुलिस ने एक ठेकेदार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता पुलिस सिपाही विशाल सोपन कामतकर (32) ने दर्ज शिकायत में बताया है कि 26 दिसंबर 2025 की रात करीब 12.30 बजे से 2.30 बजे के बीच बुद्धविहार, फुलेनगर क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से खुदाई का कार्य किया जा रहा था। यह कार्य बिना किसी अनुमति के किया जा रहा था, जिससे सड़क पर आवाजाही बाधित हुई और आसपास के नागरिकों की रात की नींद में खलल पड़ा।

शिकायत में बताया गया है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा भारी मशीनों का इस्तेमाल कर सड़क की खुदाई के दौरान तेज आवाज व शोरशराबा हो रहा है।जिससे सार्वजनिक शांति भंग हुई। साथ ही, इस अवैध कार्य के कारण दो समुदायों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका भी बनी है। जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती थी।

पुलिस ने बताया कि यह कृत्य ठाणे शहर पुलिस के विशेष शाखा द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन है, जिसमें पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने और इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद बिना अनुमति के कार्य जारी रखा गया।भिवंडी शहर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भिवंडी-निजामपुर पालिका में चुनावी सरगर्मी तेज, चौथे दिन 409 नामांकन फॉर्म बिके

अब तक 1982 फॉर्म की बिक्री, नामांकन दाखिल सिर्फ 23

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका के सार्वत्रिक चुनाव 2025-26 को लेकर शहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में उत्साह साफ नजर आया। हालांकि फॉर्म खरीदने वालों की संख्या के मुकाबले नामांकन दाखिल करने वालों की रफ्तार अब भी धीमी बनी हुई है।निर्वाचन विभाग द्वारा 27 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, शहर के सात निर्वाचन निर्णय अधिकारियों के कार्यालयों से चौथे दिन कुल 409 नामांकन फॉर्म बेचे गए, जबकि केवल 16 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

जानकारी के मुताबिक, चौथे दिन सबसे अधिक नामांकन फॉर्म निर्वाचन निर्णय अधिकारी क्रमांक-4 के क्षेत्र में बिके, जहां 135 फॉर्मों की बिक्री हुई। इसके बाद क्रमांक-3 क्षेत्र में 82, क्रमांक-2 में 44, क्रमांक-5 में 42, क्रमांक-1 में 41, क्रमांक-7 में 34 और क्रमांक-6 क्षेत्र में 31 नामांकन फॉर्म बिके।हालांकि, फॉर्म बिक्री के मुकाबले नामांकन दाखिल करने

वालों की संख्या काफी कम रही। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ, जिससे यह संकेत मिलता है कि कई इच्छुक उम्मीदवार अभी रणनीति बनाने और समीकरण साधने में जुटे हुए हैं।

गौरतलब है कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन 496 लोगों ने फॉर्म खरीदे थे। दूसरे दिन 556 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म लिया, लेकिन सिर्फ एक ने नामांकन दाखिल किया था। तीसरे दिन 515 फॉर्म बिके और 6 उम्मीदवारों ने नामांकन अर्ज दाखिल किए।अब तक कुल 1982 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदे हैं, जबकि महज 23 उम्मीदवारों ने ही नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। चुनावी जानकारों का मानना है कि नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिनों में नामांकन दाखिल करने वालों की संख्या में तेजी आने की संभावना है।

आर्केस्ट्रा बार की आड़ में अश्लील धंधा, पुलिस का छापा

मैनेजर समेत 13 गिरफ्तार, महिलाएं कराई गईं मुक्त

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी।शहर में आर्केस्ट्रा बार की आड़ में चल रहे अश्लील कारोबार पर भिवंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नारपोली पुलिस ने दापोडा रोड स्थित एक बार एंड रेस्टोरेंट/स्पा पर छापा मारकर मैनेजर समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से महिलाओं को मुक्त कराया और नकद रकम व आपत्तिजनक सामान भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक, 26 दिसंबर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि बार का मैनेजर आकाश शिवराम सूर्यवंशी महिला वेटरों और बारबालाओं के जरिए ग्राहकों को अश्लील हरकतें परोसने का धंधा चला रहा था। ग्राहकों को लुभाकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी, जबकि महिलाओं को जबरन इस अनैतिक कारोबार में धकेला जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2600 रुपये नकद, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने महिलाओं की तस्करी और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मैनेजर के अलावा ग्राहक, दलाल और सहयोगी भी शामिल हैं। पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर भेजकर उनके बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। नारपोली पुलिस ने साफ किया है कि चुनावी माहौल और कानून-व्यवस्था को देखते हुए शहर में इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

217 करोड़ देने को तैयार, महाठग सुकेश अदिति सिंह को कोर्ट में सेटलमेंट ऑफर दिया

नई दिल्ली। जेल में बंद आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष एक आवेदन दायर कर शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में 217 करोड़ रुपये देने की पेशकश की है। यह आवेदन उनके वकील अनंत मलिक के माध्यम से दायर किया गया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह पेशकश चंद्रशेखर के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई है और इसे अपराध स्वीकार करना नहीं माना जाएगा। मामले की सुनवाई 3 जनवरी, 2026 को होनी है। आवेदन में पक्षों को नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर समझौता करने की अनुमति मांगी गई है।

न्यायिक हिरासत में रह रहे चंद्रशेखर ने अदालत से शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने और यह दर्ज करने का आग्रह किया है कि समझौता प्रस्ताव वास्तविक है

चुनावी आचार संहिता में पुलिस ने की अपराधियों की धरपकड़ तेज,मची दहशत

भिवंडी में पुनः अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी मनपा क्षेत्र में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है।इसी के तहत अवैध हथियार रखने के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नारपोली पुलिस ने एक युवक को देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय शस्त्र अधिनियम एवं महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार भिवंडी के अंजुरफाटा रेलवे स्टेशन रोड स्थित सुखशांति अपार्टमेंट के सामने नारपोली पुलिस गश्त के दौरान 26 दिसंबर की शाम करीब 3.20 बजे एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ दिखाई दिया। शक के आधार पर तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस और अन्य सामग्री बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 36 हजार दो सौ रुपये बताई जा रही है।पुलिस ने इसके बाद तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।जिसका नाम अबूजैद अलीमुद्दीन शाह (उम्र 20 वर्ष), निवासी मुमताज नगर, शांतीनगर, भिवंडी के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी के पास हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस या अनुमति नहीं थी। साथ ही, ठाणे पुलिस द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन भी किया गया है।नारपोली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

भारतीय रेलवे की अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों में रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता दोगुनी करने की योजना

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

प्रमुख शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने, भीड़भाड़ कम करने और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार लाने के लिए किया जाएगाः रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव

व्यस्त स्टेशनों पर यातायात सुगम बनाने के लिए क्षमता वृद्धि के लाभों को प्राप्त करने हेतु जोन से अल्पकालिक और मध्यम अवधि के उपायों की मांग की गई है

उत्तर रेलवे के 10 रेलवे स्टेशन भी शामिल

यात्रा की मांग में लगातार हो रही तीव्र वृद्धि को देखते हुए, अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों की नई रेल गाड़ियों के संचालन की क्षमता को वर्तमान स्तर से दोगुना करना आवश्यक है। आगामी वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। वर्ष 2030 तक संचालन क्षमता को दोगुना करने के लिए निम्नलिखित कार्य शामिल होंगेः

मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं से सुसज्जित करना।

शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनलों की पहचान और निर्माण करना।

मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव सुविधाएं।

विभिन्न स्थानों पर रेल गाड़ियों की बढ़ती संख्या की व्यवस्था करने के लिए यातायात सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग उन्नयन और मल्टीट्रैकिंग के माध्यम से अनुभागीय क्षमता में वृद्धि करना।

उत्तर रेलवे के 10 रेलवे स्टेशन को भी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के लिए चिह्नित किया गया है। उत्तर रेलवे के चिह्नित दस स्टेशन निम्न हैंः

दिल्ली
लखनऊ
वाराणसी
अयोध्या
चंडीगढ़
लुधियाना
अमृतसर
जम्मू
हरिद्वार
बरेली

क्षमता को वर्ष 2030 तक दोगुना करने की योजना है, लेकिन यह आशा है कि अगले 5 वर्षों में क्षमता में क्रमिक वृद्धि की जाएगी ताकि क्षमता वृद्धि के लाभ तुरंत प्राप्त किए जा सकें। इससे आने वाले वर्षों में यातायात की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिलेगी। योजना में कार्यों को तीन श्रेणियों, अर्थात् तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया जाएगा।

नई दिल्ली स्टेशन के रीडेवलपमेंट काम का प्लान इस प्रकार हैः

मौजूदा स्टेशन बिल्डिंग को गिराकर प्लेटफॉर्म नंबर 01 और 16 के पास दो स्टेशन बिल्डिंग बनाई जाएंगी।

नई स्टेशन बिल्डिंग का एरिया मौजूदा 17274 वर्ग मीटर बिल्ट-अप एरिया के मुकाबले लगभग 109000 वर्ग मीटर होगा। अभी

रोजाना चार लाख यात्रियों को संभाला जाता है। नए स्टेशन को रोजाना सात लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन बिल्डिंगों में उचित होल्डिंग एरिया, एलिवेटेड रोड से स्टेशन बिल्डिंग तक यात्रियों के आने-जाने के लिए एप्रन

एरिया भी शामिल होंगे। इन बिल्डिंगों में पार्किंग की सुविधा होगी। शहर के ट्रैफिक और मेट्रो के विभिन्न तरीकों के साथ इंटीग्रेशन की योजना बनाई गई है। वर्तमान में जम्मूतवी स्टेशन में अपग्रेड कार्य प्रगति पर हैं जिसमें अतिरिक्त पिट लाइन, 4 अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, 7 अतिरिक्त स्टेबलिंग लाइन का निर्माण किया जा रहा हैं। इससे ज्यादा ट्रेन संचालन संभव होगा। ट्रेनों की गति में भी इजाफा होगा और ट्रेन मेंटिनेंस भी बेहतर होगी।

बरेली जंक्शन पर भी यार्ड रिमॉडलिंग प्रस्तावित हैं। यार्ड रिमॉडलिंग के पश्चात, यह स्टेशन 24 कोच वाली ट्रेन का परिचालन आसानी से कर सकेगा। इसके अलावा, सिक लाइन, पिट लाइन का विस्तार होगा। इन कार्यों से ज्यादा ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा, साथ ही ट्रेन मेंटिनेंस का कार्य और बेहतर होगा।केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'हम यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए विभिन्न शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार कर रहे हैं और अनुभागीय एवं परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इस कदम से हमारे रेलवे नेटवर्क का उन्नयन होगा और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार होगा।'

मनोरंजन

अल्लू अर्जुन समेत 24 पर पुलिस का शिकंजा, चार्जशीट दाखिल

मुंबई। दिसंबर 2024 में हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ के संबंध में दायर आरोपपत्र में अभिनेता अल्लू अर्जुन और उनकी सुरक्षा टीम सहित 23 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। हाल ही में दायर आरोपपत्र में थिएटर प्रबंधन को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि अर्जुन को आरोपी संख्या 11 के रूप में नामित किया गया है। इस आयोजन के

दौरान भीड़ नियंत्रण में हुई चूक के लिए थिएटर प्रबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया गया है।

इससे पहले, पिछले साल 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में 'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मचने से 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था। इस घटना के बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। यह भगदड़ तब मची जब प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसक जमा हो गए थे। घटना के बाद शहर की पुलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मृतक महिला के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। 13 दिसंबर, 2024 को भगदड़ के संबंध में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था और तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद अगले दिन उन्हें रिहा कर दिया गया था। बाद में उन्हें नियमित जमानत मिल गई।

'बिग बॉस 19' फेम तान्या मित्तल का बड़ा खुलासाः मैं एक कंडोम फैक्ट्री की मालकिन हूं, ऐसे होती है क्वालिटी चेकिंग

'बिग बॉस 19' शो का समापन हो गया है, लेकिन इसके कंटेस्टेंट अभी चर्चाओं में बनें हुए। इस बीच, सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक तान्या मित्तल हैं। अब उनको विनर की ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन अपने आत्मविश्वास और आलोचनाओं के बावजूद भी बिना कैमरे के सामने मुस्कुराने के अंदाज से उन्होंने सबका दिल जीता है। तान्या मित्तल के दौलत के बारे झूठे दावे किए और उनके इस खुलासे पर हंसे कि उनके चारों ओर कई बॉडीगार्ड रहते हैं, उनके पास महंगी गाड़ियां हैं और वे आलीशान घर में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कंडोम फैक्ट्री की मालकिन होने का चौंकाने वाला खुलासा किया है। इससे पहले तान्या मित्तल यह कह चुकी थीं कि उनका खुद का एक कपड़ों का ब्रांड है। लेकिन इसके साथ-साथ उनका एक कंडोम निर्माण यूनिट भी है, जो उनकी आय का एक अहम स्रोत माना जाता है। न्यूज पिंच को दिए गए इंटरव्यू में तान्या मित्तल ने अपनी कंडोम फैक्ट्री का भ्रमण कराया, जहां उन्होंने बताया कि कंडोम की पैकेजिंग, गुणवत्ता जांच (टेस्टिंग) और अन्य प्रक्रियाएं किस तरह की जाती हैं।

तान्या मित्तल की कंडोम की फैक्ट्री

तान्या मित्तल ने आगे बताया कि उनकी फैक्ट्री में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं और इससे रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि उनकी फैक्ट्री का चुनाव थोड़ा अलग है और कई लोग इस बारे में बात करने से कतराते हैं। तान्या ने अपने फैंस को प्रोडक्शन एरिया को भी दिखाया और फैक्ट्री में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक भी दिखाई। तान्या ने कंडोम उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली मशीनरी दिखाई और बताया कि इन्हें दुनिया के कई हिस्सों से इक्ट्ठा किया जाता है फिर आयात किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने लैब का भी दौरा कराया, जहां प्रोडक्ट्स की जांच की जाती है, बताया कि जांच कैसे होती है।

सलमान खान पर उठाए सवाल

तान्या ने बताया कि सलमान ने लोगों से उनके लिए डटकर लड़ाई लड़ी और पूरा साथ दिया, जबकि उन्हें उनकी सच्चाई का पता भी नहीं था। उन्होंने बिना किसी संदेह के उन पर विश्वास किया। इसी कारण एक 'फर्जी' लड़की का समर्थन करने को लेकर उन्हें निशाना बनाया गया और ट्रोल किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार अपमान सहना पड़ा। घर के भीतर छह दिनों तक उनके साथ प्रताड़ना होती रही और वीकेंड पर आने वाला हर एक व्यक्ति उन्हें और ज्यादा परेशान करता था। वह बार-बार उन्हें तंग करता और मानसिक रूप से परेशान करता रहता था।

ग्वालियर में तान्या मित्तल का घर

बिग बॉस के बाद तान्या मित्तल का ग्वालियर में भव्य स्वागत किया गया है। सोशल मीडिया पर परिवार के साथ उनके मिलने के भावुक वीडियों काफी छाए हुए है। हालिए में तान्या के घर का एक वीडियो मिला, जिसके बाहर कई कारें खड़ी थीं। वीडियो में उनके एंट्री गेट की झलक भी दिखाई दी, जो कि गेंदे के फूलों से सजा हुआ था, एक बड़ा लॉन था और रईसी साफ दिखाई दे रही थी।

दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना आउट; जयदीप अहलावत की एंट्री पर प्रोड्यूसर का बड़ा बयान, 'बेहतर एक्टर और इंसान मिला'

मुंबई।अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम' फिल्म का क्रेज फैंस के सिर पर चढ़ा हुआ है। इस फिल्म के दूसरा पार्ट भी चुका हैं, अब अगले साल 2 अक्टूबर, 2026 को 'दृश्यम 3' रिलीज होने के लिए तैयार है। दृश्यम 3 को लेकर फैंस भी काफी एक्ससाइटेड नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक खबर आई हैं कि इस फिल्म से अक्षय खन्ना को एग्जिट कर दिया है, जिसके बाद दर्शक भी थोड़ा दुखी नजर आ रहे हैं। दरअसल, पक्की खबर तो यह है कि 'पाताल लोक' के एक्टर जयदीप अहलावत अब इस मूवी नजर आ सकते हैं। जयदीप अहलावत ने 'धुरंधर' एक्टर को रिप्लेस किया है और इसकी पुष्टि खुद प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने की है।

इस बार अजय देवगन की 'दृश्यम 3' में श्रिया सरन, तब्बू और इशिता दत्ता बतौर स्टारकास्ट नजर आने वाली है। फिल्म की कहानी कुछ ज्यादा ही रोमांचक होने वाली है, जैसा कि इसके टीजर में एक्टर ने बताया था। लेकिन अब यह चर्चा हो रही है कि फीस के कारण अक्षय खन्ना जो दूसरे पार्ट में पुलिस के रोल में दिखे थे, वो नहीं होंगे। उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने पुष्टि की है कि जयदीप अहलावत 'दृश्यम 3' में शामिल होंगे। 'दृश्यम एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्षय फिल्म में हैं या नहीं। अब अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत को रिप्लेस किया है। भगवान की कृपा से हमें अक्षय से बेहतर एक्टर मिला है औ? सबसे जरुरी बात, अक्षय से बेहतर इंसान भी मिला है। मैंने जयदीप के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक, आक्रोश (2010) का निर्माण किया था। मुझे अक्षय खन्ना के व्यवहार के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। मैं कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं। मैंने उन्हें पहले ही कानूनी नोटिस भेज दिया है और अभी तक उन्होने इसका जवाब नहीं दिया है।'

बीसीसीआई ने किया अंडर-19 विश्व कप टीम का एलान, आयुष को मिली कप्तानी; वैभव भी हिस्सा

नई दिल्ली। अंडर-19 विश्व कप के लिए शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)ने टीम इंडिया का एलान कर दिया। इस टीम की कमान आयुष म्हात्रे को सौंपी गई है, जबकि विहान मल्होत्रा को उपकप्तानी मिली है। इस टीम में विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है। इससे पहले टीम इंडिया अगले साल की शुरुआत में तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। अंडर-19 विश्व कप के लिए चुनी गई टीम ही इस सीरीज में भी खेलेगी।

भारत ग्रुप बी में शामिल

अंडर-19 विश्व कप का आयोजन 15 जनवरी से छह फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 16 टीमों का चार ग्रुप में बांटा गया है। पांच बार की अंडर-19 विश्व कप विजेता भारतीय टीम को ग्रुप बी में न्यूजीलैंड, अमेरिका और बांग्लादेश के साथ शामिल किया गया

है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 जनवरी से अमेरिका के खिलाफ मुकाबले से करेगी। इसके बाद टीम का सामना 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हरारे में खेला जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वैभव होंगे टीम के कप्तान

इससे पहले टीम इंडिया तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। अंडर-19 वनडे विश्व कप से पहले यह सीरीज भारत के लिहाज से काफी अहम है। बीसीसीआई ने बताया कि आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा इस सीरीज में नहीं खेलेंगे। दोनों कलाई की चोट से जूझ रहे हैं। ऐसे में बोर्ड ने वैभव सूर्यवंशी को कप्तान और आरोन जॉर्ज को उपकप्तान नियुक्त किया है। तीनों मुकाबले क्रमशः 3 जनवरी, 5 जनवरी और 7 जनवरी को विलोमोर पार्क में खेले जाएंगे।

दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीमः वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आरोन जॉर्ज (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार।

अंडर-19 वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीमः आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस.. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन।

एशेज में स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कंगारू बने

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डर को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ देश के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए चौथे एशेज टेस्ट के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। पहली पारी में जोश टोंग के हाथों आउट होते हुए वह सिर्फ नौ रन ही बना सके, लेकिन अगले मैच में उन्होंने 39 गेंदों में एक चौके की मदद से 24 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने एक आसान लक्ष्य पेश करते हुए अकेले ही डटकर मुकाबला किया। इंग्लैंड के खिलाफ 40 टेस्ट मैचों में स्मिथ ने 72 पारियों में 55.51 के औसत से 3,553 रन बनाए हैं, जिनमें 12 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 239 रन है। इंग्लैंड के खिलाफ 47 टेस्ट मैचों में, बॉर्डर ने 82 पारियों में 56.31 के औसत से 3,548 रन बनाए हैं, जिनमें आठ शतक, 21 अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 200ङ शामिल हैं। इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी दिग्गज डॉन ब्रैडमैन हैं, जिन्होंने 37 टेस्ट मैचों में 63 पारियों में 89.78 के औसत से 5,028 रन बनाए हैं, जिनमें 19 शतक और 12 अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 334 शामिल हैं।

मैच की बात करें तो, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना। जोश टोंग (5/45) ने एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड के लिए पहली बार पांच विकेट लिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया 45.2 ओवर में 152 रन पर ऑल आउट हो गई। माइकल नेसर (49 गेंदों में 35 रन, सात चौकों के साथ) और उस्मान ख्वाजा (52 गेंदों में 29 रन, दो चौकों के साथ) ऑस्ट्रेलिया के लिए शीर्ष स्कोरर रहे। नेसर ने कैमरून ग्रीन (17) के साथ अर्धशतकीय साझेदारी भी की, लेकिन रन आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई।

बीपीएल में हुआ दुखद हादसा, ढाका टीम के सहायक कोच का दिल का दौरा पड़ने से निधन

ढाका। बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) के दौरान एक दुखद हादसा हो गया। ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली जाकी का शनिवार को सिलहट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में राजशाही वॉरियर्स के खिलाफ बीपीएल के अपने उद्घाटन मैच से कुछ क्षण पहले मैदान पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह दुखद घटना मैच के निर्धारित समय से कुछ ही पहले घटी, जब टीम की तैयारियों के दौरान जाकी अचानक बीमार पड़ गए।

मैदान पर गिर पड़े थे जाकी

वे मैदान पर गिर पड़े और वहां मौजूद चिकित्सा कर्मियों ने तुरंत उनकी सहायता की। उन्हें मैदान पर ही सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) दिया गया, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। ढाका कैपिटल्स ने एक आधिकारिक बयान में घटना की पुष्टि करते हुए कहा, ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली जाकी अभ्यास के दौरान बीमार पड़ गए और मैदान पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत सीपीआर दिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जाकी को बाद में गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज जारी रखा। हालांकि, तमाम चिकित्सीय प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और भारतीय समयानुसार दोपहर 12.30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

दोनों टीमों के सदस्यों ने जाकी को दी श्रद्धांजलि

अपने शांत स्वभाव और खेल की गहरी समझ के लिए जाने जाने वाले जाकी ने टूर्नामेंट से कुछ ही दिन पहले मीडिया से बात की थी, जिसमें उन्होंने ढाका टीम की योजनाओं की रूपरेखा बताई थी और पहले मैच से पहले खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम किया था। उनके निधन की खबर के बाद ढाका कैपिटल्स और राजशाही वॉरियर्स दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने दौरान एक मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

बांग्लादेश क्रिकेट का जाना पहचाना नाम थे जाकी

महबूब अली जाकी बांग्लादेश क्रिकेट में एक जाना पहचाना नाम थे। बीपीएल 2026 में ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच के रूप में अपनी भूमिका के साथ-साथ उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खेल विकास विभाग में विशेषज्ञ तेज गेंदबाजी कोच के रूप में भी कार्य किया। वे 2020 में अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली बांग्लादेश टीम के तेज गेंदबाजी कोच भी थे। बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने जाकी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, कोच जाकी के निधन की खबर से मैं बहुत दुखी और स्तब्ध हूं। मैं उन्हें अपने पेशेवर क्रिकेटर के शुरुआती दिनों से जानता हूं।

टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग कोच की तलाश कर रहा है बीसीसीआई? इस पूर्व बल्लेबाज के साथ किया था संपर्क

नई दिल्ली। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का सीमित ओवर में अच्छा रिकॉर्ड है और उनके नेतृत्व में टीम ने एक आईसीसी और एक एसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है। लेकिन सेना देशों के खिलाफ 10 टेस्ट मैच गंवाने के बाद लाल गेंद के क्रिकेट में कोच के तौर पर गंभीर की शैली पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में अहम पद पर मौजूद किसी ने वीवीएस लक्ष्मण से अनौपचारिक तौर पर बातचीत की थी और यह जानने की कोशिश की थी कि क्या वह लाल गेंद की टीम का कोच बनने में रुचि रखते हैं?

ऊिह्गहु ज्ञादे

गंभीर के अनुबंध पर होगा पुनर्विचार?

यह समझा जा रहा है कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज लक्ष्मण बंगलूरू स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हेड ऑफ क्रिकेट के पद से ही संतुष्ट हैं। गंभीर का बीसीसीआई के साथ अनुबंध 2027 वनडे विश्व कप के अंत तक है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि भारत के टी20 विश्व कप में प्रदर्शन के आधार पर इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। टी20 विश्व कप की शुरुआत पांच सप्ताह के बाद होनी है।

विज्ञापन

ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई के गलियारों में अभी भी इस बात पर बहस जारी है कि क्या गंभीर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 चक्र के शेष नौ टेस्ट मैचों के लिए लाल गेंद टीम की कमान संभालने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ खेली थी। 2026 में भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने हैं और अक्तूबर में न्यूजीलैंड का दौरा करना है। फिर जनवरी-फरवरी 2027 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है।

टी20 विश्व कप के प्रदर्शन पर काफी कुछ निर्भर

बीसीसीआई के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा, भारतीय क्रिकेट के गलियारों में गंभीर को जबरदस्त समर्थन प्राप्त है और जाहिर है कि अगर भारत टी20 विश्व कप का खिताब बरकरार रखता है या कम से कम फाइनल तक पहुंचता है तो वह बिना किसी रुकावट के अपना काम जारी रख सकेंगे। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गंभीर टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी भूमिका जारी रखते हैं। उनका फायदा यह है कि लाल गेंद के प्रारूप में बहुत अधिक वैकल्पिक विकल्प नहीं हैं, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण सीनियर टेस्ट टीम को कोचिंग देने में रुचि नहीं रखते हैं।

गिल के बाहर होने से खिलाड़ियों में बढ़ी बैचेनी

भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी हाल के दिनों में हालात अच्छे नहीं दिख हैं और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो गंभीर के दौर में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि राहुल द्रविड़ के कार्यकाल के दौरान खिलाड़ियों को खुद को साबित करने के लिए लंबा समय मिलता रहा। शुभमन गिल को टी20 विश्व कप टीम से बाहर किए जाने में गंभीर की भूमिका स्पष्ट रूप से झलकती है और इसने निश्चित रूप से कई खिलाड़ियों को यह विश्वास दिला दिया है कि अगर भारतीय क्रिकेट के अगले स्टार खिलाड़ी को दरकिनार किया जा सकता है तो अगली बार टीम से बाहर होने की लिस्ट में किसी का भी नाम हो सकता है।

बीसीसीआई नीतिगत फैसले लेने में हमेशा समय लेता है और अगर कैलेंडर पर नजर डालें तो टी20 विश्व कप के बाद दो महीने तक आईपीएल भी होना है।

मेलबर्न टेस्ट दो दिन में समाप्त, टूटा 130 साल पुराना रिकॉर्ड; इंग्लैंड ने खत्म किया 5468 दिनों का सूखा

मेलबर्न। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया एशेज टेस्ट सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया और इसी के साथ क्रिकेट इतिहास में कई बड़े रिकॉर्ड टूट गए। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर न केवल बॉक्सिंग डे टेस्ट जीता, बल्कि 5468 दिनों से चला आ रहा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीत का सूखा भी खत्म कर दिया। इससे पहले इंग्लैंड ने आखिरी बार सात जनवरी 2011 को सिडनी में टेस्ट मैच जीता था।

मेलबर्न टेस्ट में क्या हुआ?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट को इंग्लिश टीम ने दूसरे दिन ही चार विकेट से अपने नाम किया। 175 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने छह विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। हालांकि, इस हार से सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑस्ट्रेलिया शुरुआती तीन टेस्ट जीतकर पहले ही अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है। इंग्लैंड ने इस जीत के साथ आखिरकार जीत का स्वाद चखा और सीरीज की स्थिति फिलहाल 3-1 है।

मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उनके फैसले को इंग्लिश गेंदबाजों ने सही साबित किया और ऑस्ट्रेलियाई पारी को 152 रन पर समेट दिया। जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 110 रन पर सिमट गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को 42 रन की बढ़त हासिल हुई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 34.3 ओवर में 132 रन पर ऑलआउट हो गई। 42 रन को मिलाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कुछ बढ़त 174 रन की हुई। 175 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 32.2 ओवर में छह विकेट गंवाकर हासिल कर लिया।

यह जीत इंग्लैंड के लिए ही नहीं, बल्कि कप्तान जो रूट और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के लिए भी खास रही। रूट ने ऑस्ट्रेलिया में 18 टेस्ट मैचों के बाद पहली जीत दर्ज की, जबकि स्टोक्स को 13 टेस्ट के बाद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर जीत नसीब हुई। यह आंकड़े बताते हैं कि यह दौरा इंग्लैंड के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। हालांकि, मेलबर्न टेस्ट में आखिरकार बैजबॉल का खेल काम आया और इंग्लैंड की टीम ने 5.50 के रन रेट से रन बनाए।

130 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

मेलबर्न टेस्ट सिर्फ 852 गेंदों में समाप्त हो गया। यह एशेज इतिहास के सबसे तेज खत्म होने वाले पांच टेस्ट मैचों में शामिल हो गया। इससे पहले 1895 में सिडनी टेस्ट 911 गेंदों में समाप्त हुआ था। यानी करीब 130 साल बाद इतना छोटा टेस्ट मैच देखने को मिला।

इंडिगो उड़ान संकट की जांच करने वाली समिति ने DGCA को रिपोर्ट सौंपी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने के मामले की जांच करने वाली चार-सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट विमानन नियामक डीजीसीए को सौंप दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के संयुक्त महानिदेशक संजय के. ब्रम्हाणे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन पांच दिसंबर को किया गया था।

समिति को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह उन परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा करे, जिनकी वजह से इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें कई दिनों तक रद्द हुई थीं। अधिकारी ने कहा कि जांच समिति ने शुक्रवार शाम अपनी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंप दी। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट की प्रतियां नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू और नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा के कार्यालय को भी भेजी गई हैं। हालांकि, रिपोर्ट के निष्कर्षों का ब्योरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

इस समिति में ब्रम्हाणे के अलावा डीजीसीए के उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन कपिल मांगलिक और उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन रामपाल शामिल थे। इस महीने के शुरुआती सप्ताह में इंडिगो की उड़ानें बड़े पैमाने पर निरस्त हुई थीं। इस दौरान एक दिन 1,600 से अधिक उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी थीं। इसके अलावा बड़ी संख्या में उड़ानें कई घंटों की देरी से भी रवाना हुईं जिससे देशभर के हवाई अड्डों पर यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। चालक दल के सदस्यों की तैनाती एवं विश्राम से संबंधित नए मानकों को लागू करने के लिए इंडिगो ने समय पर तैयारी नहीं की थी जिसकी वजह से यह व्यापक गतिरोध पैदा हुआ। उड़ान बाधाओं के बाद डीजीसीए ने इंडिगो को अपना शीतकालीन उड़ानों की संख्या में 10 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्देश दिया था।

साथ ही, एयरलाइन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) इसिड्रे पोर्केरास को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए।

दक्षिण के मंदिर पथ : मनमाड़ से भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम की नई आध्यात्मिक रेल यात्रा

पर्यटक मनमाड़, नासिक रोड, कल्याण, लोनावला, पुणे, सातारा तथा मिरज स्टेशनों से इस विशेष रेलगाड़ी में चढ़ और उतर सकेंगे। यह रेलगाड़ी अठारह फ़रवरी दो हज़ार छब्बीस को मनमाड़ से प्रस्थान करेगी।

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, जो एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ने मनमाड़ से भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के अंतर्गत 'दक्षिण के मंदिर पथ' नामक एक विशिष्ट आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ किया है। इस यात्रा के माध्यम से पहली बार महाराष्ट्र सहित देश के अन्य भागों के श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक एवं विरासत स्थलों की बारह रात और तेरह दिन की अविस्मरणीय तीर्थयात्रा का अवसर प्राप्त होगा।

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के पश्चिम क्षेत्र, मुंबई के समूह महाप्रबंधक श्री गौरव झा ने बताया कि यह विशेष संयुक्त वातानुकूलित तथा अवातानुकूलित रेलगाड़ी तीर्थयात्रियों और विरासत प्रेमियों को दक्षिणी राज्यों के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थलों तक सुगम एवं सुव्यवस्थित यात्रा कराएगी। इस यात्रा में मुरुडेश्वर, गुरुवायूर, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, कांचीपुरम तथा महाबलीपुरम जैसे प्रतिष्ठित गंतव्य सम्मिलित हैं। प्रत्येक स्थान आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुपम संगम प्रस्तुत करता है, जहाँ मुरुडेश्वर के भव्य शिव मंदिर, विवेकानंद

शिला स्मारक की शांति तथा महाबलीपुरम के ऐतिहासिक तट मंदिर की भव्यता के दर्शन कराए जाएंगे।

यात्री अर्थव्यवस्था शयनयान श्रेणी, मानक तृतीय वातानुकूलित श्रेणी तथा सुविधा द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा का चयन कर सकते हैं। यह विशेष रेलगाड़ी लगभग सात सौ पचास यात्रियों की क्षमता के साथ संचालित की जाएगी। मनमाड़, नासिक रोड, कल्याण, लोनावला, पुणे, सातारा और मिरज स्टेशनों पर चढ़ने तथा उतरने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु इस यात्रा का लाभ उठा सकें।

यह संपूर्ण पैकेज यात्रियों को निश्चिंत एवं सुविधाजनक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसमें वातानुकूलित तथा अवातानुकूलित डिब्बों में आरामदायक रेल यात्रा, बजट होटलों में दो, तीन अथवा चार व्यक्तियों के साझा आधार पर ठहराव, पूरी यात्रा के दौरान शुद्ध शाकाहारी भोजन, वातानुकूलित एवं अवातानुकूलित वाहनों द्वारा स्थानीय भ्रमण, समग्र यात्रा बीमा तथा समन्वय के लिए समर्पित पर्यटन प्रबंधकों की सेवाएँ सम्मिलित हैं।

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के पश्चिम क्षेत्र के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर ए0 के0 सिंह ने बताया कि यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है तथा सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियाँ अपनाई गई हैं।

'दक्षिण के मंदिर पथ' यात्रा के लिए पैकेज शुल्क अर्थव्यवस्था श्रेणी के लिए तेईस हज़ार तीन सौ सत्तर रुपये, मानक तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के लिए छत्तीस हज़ार नौ सौ नब्बे रुपये तथा सुविधा द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के लिए अड़तालीस हज़ार सात सौ साठ रुपये निर्धारित किया गया है।

इस यात्रा की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के पर्यटन पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए यात्री मोबाइल नंबर आठ दो आठ सात नौ तीन एक आठ आठ छह पर संपर्क कर सकते हैं अथवा इलेक्ट्रॉनिक डाक के माध्यम से संदेश भेज सकते हैं।

यह नई पहल न केवल भारत के आध्यात्मिक पर्यटन को नई दिशा प्रदान करती है, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क को भी सुदृढ़ बनाती है तथा यात्रियों को सुविधा, सुरक्षा और श्रद्धा के साथ दक्षिण भारत की आत्मा से परिचित होने का अवसर प्रदान करती है।

उच्चरक्तचाप से ग्रस्त लोग ठंड में सुबह न टहलें - डॉ जी एस तोमर

गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन झूँसी सेक्टर की बैठक हुई सम्पन्नः ठंड से बचाव के आयुर्वेदिक नुस्खे बताए गए,ग्रुप और सेक्टर व्यवस्था को मजबूत बनाने पर दिया गया जोर

प्रयागराज। आज पेंशनर्स के झूँसी सेक्टर की बैठक संजीवनी सेवालय में डॉ जी एस तोमर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।डॉ तोमर ने वृद्धा अवस्था में ठंड से बचाव के लिए आयुर्वेदिक नुख्सों और कुछ आसान योग के बारे में पेंशनर्स को बताया।पूर्व मण्डलायुक्त आर एस वर्मा ने पेंशनर्स को ग्रुप और सेक्टर व्यवस्था को मजबूत बनाने और आपस मे छोटे छोटे ग्रुप की बैठक नियमित रूप से कर, आपसी सहयोग और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होने की सलाह दी।यह भी कहा पहले हम अपनी जो समस्याए आपसी सहयोग से हल कर सकते उसे करे।आगे की समस्याओं के लिए एसोसिएशन भरपूर प्रयास कर रहा है।आज तीन नए सदस्य बने जिनका स्वागत किया गया। पांच सदस्यों का जन्मदिन दिसंबर में होने पर और 3 सदस्यो को 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सम्मानित किया गया।बैठक में पूर्व कमिश्नर वी के सिंह,डॉ सुधा प्रकाश,और डॉ वी के श्रीवास्तव और डॉ परशुराम मौर्य ने भी अपने बहुमूल्य विचार रखे।कार्यक्रम का सफल संचालन झूसी सेक्टर प्रभारी आर डी कुशवाहा ने किया। डॉ अरबिंद श्रीवास्तवा और अशोक कुमार ने सुंदर कविता सुनाई।इसके अतिरिक्त प्रमुख रूप से आर डी प्रसाद,देवी दयाल,जी डी यादव, पी आर मौर्य,आदि बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्तित रहे।

आर एस वर्मा
आई ए एस(से नि)
अध्यक्ष, गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन।

करावली उत्सव में बड़ा हादसा, मंगलूरू के मेले में अचानक खराब हुआ झूला; दो बच्चे घायल, जांच के आदेश

बंगलूरू। कर्नाटक के तटीय शहर मैंगलुरु में करावली उत्सव के दौरान लगे मनोरंजन झूले में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। जायंट व्हील के अचानक खराब होने से एक व्यक्ति और उसके दो बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की आशंका जताई है।

पुलिस के मुताबिक यह हादसा 24 दिसंबर को करावली उत्सव मैदान में हुआ। शहर निवासी के. मोहन मुलाली ने शिकायत में बताया कि जायंट व्हील तेज रफ्तार से चलने लगा। इसी दौरान जिस केबिन में वह और उनके बच्चे बैठे थे, वह अचानक नीचे गिरा और दूसरे केबिन से टकरा गया। हादसे में तीनों को चोटें आईं।

झूले में खराबी और टूटे दरवाजे

शिकायत के अनुसार, झूला चलते समय केबिन के दरवाजे टूट गए। इसके कारण सवारी कर रहे लोग केबिन के अंदर ही बार-बार उछलते और टकराते रहे। पीड़ित का आरोप है कि यह साफ तौर पर झूले के रखरखाव में भारी लापरवाही को दर्शाता है। घटना के वक्त वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए।

मौके पर नहीं मिली चिकित्सा सहायता

पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि हादसे के बाद मौके पर न तो प्राथमिक उपचार की सुविधा थी और न ही एंबुलेंस तुरंत उपलब्ध कराई गई। आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायल पिता और बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि जिला प्रशासन से जुड़े एक अधिकारी ने दावा किया कि उत्सव स्थल पर तैनात एंबुलेंस उस समय किसी अन्य आपात स्थिति में लगी हुई थी।

पुलिस की जांच और प्रशासन की सफाई

मैंगलुरु पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा कि शिकायत से प्रथम दृष्टया लापरवाही और खराब रखरखाव के संकेत मिलते हैं। झूला संचालकों से सभी दस्तावेज मांगे गए हैं। यह भी जांच की जा रही है कि क्या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ है। प्रशासन ने सभी मनोरंजन झूलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही है।

कानूनी कार्रवाई और पीड़ित की मांग

पुलिस ने साफ किया है कि यदि जांच में सार्वजनिक सुरक्षा और लापरवाही से जुड़े कानूनों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो मामला दर्ज किया जाएगा। पीड़ित के. मोहन मुलाली ने जायंट व्हील को तत्काल बंद करने और सभी मनोरंजन झूलों का अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की है। पुलिस ने कहा है कि जन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

केरल के सरकारी अस्पताल में हुआ हार्ट ट्रांसप्लांटः नेपाली महिला को मिला नया जीवन, स्वास्थ्य मंत्री ने जाना हाल

कोच्चि (केरल)। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को एर्नाकुलम जनरल अस्पताल का दौरा किया और नेपाल की एक महिला के हाल का जायजा लिया, जिनका हाल ही में यहां हृदय प्रत्यारोपण (हार्ट ट्रांसप्लांट) हुआ था।

यह पहली बार था जब राज्य की किसी जिला स्तर की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में ऐसी सर्जरी हुई। दुर्गा कामी (21 वर्षीय) एक दुर्लभ आनुवंशिक हृदय रोग हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी से पीड़ित थीं। उनका 22 दिसंबर को सफल हार्ट ट्रांसप्लांट कर लिया। उन्हें कोल्लम के शिबु का अंग मिला, जो सड़क दुर्घटना के बाद मस्तिष्क मृत घोषित किए गए थे।

मंत्री ने कहा कि उन्होंने आईसीयू के बाहर से कामी को देखा और उनके भाई और अस्पताल में मौजूद अन्य लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मरीज की हालत धीरे-धीरे बेहतर हो रही है। वीना जॉर्ज ने कहा कि उन्होंने डॉक्टरों के साथ चर्चा की और मेडिकल टीम मरीज को सर्वोत्तम इलाज सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की एक टीम रोजाना मरीज की स्थिति

की समीक्षा कर रही है और सामान्य अस्पताल की टीम के साथ मिलकर काम कर रही है।

मंत्री ने कहा, यह ऐतिहासिक घटनाक्रम है। जिला स्तर के सरकारी अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट करने से ऐसे उपचार और सुपरस्पेशलिटी सुविधाओं का विकेंद्रीकरण होगा, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक अन्य अहम पहलू किफायती इलाज भी है। जब जिला अस्पतालों में सुपरस्पेशलिटी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो मरीजों को अन्य जगह खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्री ने याद दिलाया कि दिसंबर 2021 में एर्नाकुलम सामान्य अस्पताल राज्य का पहला जिला अस्पताल बना, जिसने खुली हार्ट सर्जरी की थी।

दौरे के दौरान विधायक टीजे विनोद, जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. शीजा, के-एसओटीटीओ के कार्यकारी निदेशक डॉ. नोबल ग्रेशियस और अस्पताल अधीक्षक डॉ. साहिरशा भी मौजूद थे।

उपचार की उच्च लागत के कारण कामी और उनके छोटे भाई को एक मलयाली केरल लेकर आया। यह व्यक्ति उस अनाथालय का संचालन करता है, जहां वे रहते थे।

हालांकि कामी ने आठ महीने पहले केरल स्टेट ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (के-एसओटीटीओ) में पंजीकरण कराया था और मिलान करने वाले दाता की प्रतीक्षा कर रही थीं। लेकिन शुरू में उन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वह भारतीय नागरिक नहीं थीं। बाद में उन्होंने केरल हाईकोर्ट का रुख किया, जिसने उन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल करने का निर्देश दिया।

'कट्टरपंथ का उभार बांग्लादेश की राजनीति के लिए खतरनाक', पूर्व राजदूत बोले- यूनुस ने निराश किया

नई दिल्ली। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता का माहौल है। हाल ही में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाएं भी बढ़ीं। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर भारत के पूर्व राजदूत सुरेश के गोयल ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ का उभार हालात को बेहद मुश्किल बना रहा है।

पूर्व राजदूत ने कहा, 'मुझे लगा था कि मोहम्मद यूनुस की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक छवि है और वे बांग्लादेश की राजनीति को बेहतर तरीके से नियंत्रित करेंगे। लेकिन साफ है कि उनके फैसले दूसरों से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। ये बाहरी तत्व, जिहादी तत्वों का बढ़ता प्रभाव है, जो बांग्लादेश की राजनीति को जटिल बना रहा है। बांग्लादेश में हालात और बिगड़ रहे हैं और जितना हमने सोचा था, उससे भी ज्यादा जटिल हो रहे हैं।'

तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने पर पूर्व राजदूत ने कहा, 'यह एक अच्छी बात है क्योंकि अगर बीएनपी चुनावों में हिस्सा लेती है, तो यह साबित होगा कि चुनाव देश में लोकतांत्रिक शासन की वापसी की एक सच्ची कोशिश है। लेकिन साथ ही, उन्होंने अवामी लीग पर सिर्फ इसलिए प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि वे शेख हसीना को वापस नहीं आने देना चाहते। मुझे उम्मीद है कि चुनाव मजाक नहीं बनेंगे।'

उस्मान हादी की कब्र पर तारिक रहमान ने की दुआ

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (ँञ) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने शनिवार को ढाका यूनिवर्सिटी का दौरा किया और भारी सुरक्षा के बीच मारे गए छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की कब्र पर दुआ की। 60 वर्षीय बीएनपी नेता ने ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल मस्जिद के पास स्थित बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र पर भी दुआ की। हादी को 20 दिसंबर को नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया गया था। रहमान ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता हादी की कब्र पर श्रद्धांजलि दी, जिनकी इस महीने की शुरुआत में एक हमले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। रहमान गुरुवार को लंदन से बांग्लादेश लौटे, जिससे 2008 में शुरू हुआ उनका लंबा स्व-निर्वासन खत्म हो गया।

मौलाना पर ईडी का एक्शन, लंदन में साजिश, यूपी के मदरसे से ले रहा था सैलरी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और कई वर्षों से यूनाइटेड किंगडम में रह रहे मदरसे के शिक्षक शम्सुल हुदा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा की गई जांच के बाद मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के अनुसार, यह मामला गंभीर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें कथित तौर पर विदेश में रहते हुए सरकारी वेतन और पेंशन लाभ प्राप्त करना, विदेशी संस्थाओं से संदिग्ध संबंध और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।

विदेश में रहते हुए सरकारी वेतन का लाभ

जांच में पता चला कि शम्सुल हुदा को 12 जुलाई, 1984 को आजमगढ़ के मुबारकपुर स्थित दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, 2007 में विदेश चले जाने के बावजूद, उन पर आरोप है कि उन्हें निम्नलिखित लाभ मिलते रहेः

नियमित वेतन वृद्धि

बिना सत्यापन के सरकारी लाभ

2017 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति

सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भुगतान

अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान अनिवार्य सेवा रिकॉर्ड सत्यापन नहीं किया गया, जिससे आरोपी को विदेश में रहते हुए भी सरकारी धन प्राप्त होता रहा।

धार्मिक शिक्षा की आड़ में फैला रहा था कट्टरपंथ

मौलाना धार्मिक शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था और अवैध फंडिंग नेटवर्क चला रहा था। उसने अपनी एनजीओ 'राजा फाउंडेशन' और निजी खातों के जरिए मदरसों में पैसे भेजे। आजमगढ़ और संत कबीर नगर में दो मदरसे भी स्थापित किए थे, जिनका पंजीकरण बाद में रद्द कर दिया गया। उसके पाकिस्तान स्थित कट्टरपंथी संगठनों से संपर्क होने की आशंका है।

बॉर्डर पर फटा चीनी रॉकेट लॉन्चर, सैनिकों के उड़ गए चिथड़े

नई दिल्ली। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। यह बात अक्सर चीनी सामान को लेकर कही जाती है। भले ही चीन खुद को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति कहता हो, लेकिन सच यह है कि उसके बनाए सामानों की गुणवत्ता पर आज भी दुनिया को भरोसा नहीं है। आपने देखा होगा कि हाल ही में बॉर्डर पर तनाव के दौरान जब पाकिस्तान ने चीनी मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमला करने की कोशिश की थी, तो कैसे भारत के हथियारों को आगे ये सब फुस हो गए थे। जिसके बाद दुनिया भर में चीन और उसके हथियारों की भारी बेइज्जती हुई थी।

एक बार फिर से थाईलैंड कंबोडिया युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कंबोडिया ने भी पाकिस्तान की तरह चीन के हथियारों का इस्तेमाल करके बड़ी गलती कर दी। कंबोडिया चीन के बने रॉकेट लांचर से थाईलैंड पर गोले दाग रहा था। लेकिन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ने धोखा दे दिया। ऐसा विस्फोट हुआ कि आठ कंबोडियाई सैनिक मारे गए। चीन के हथियारों का यह लाइव डेमो है। यूं ही नहीं चीन के सामान दुनिया

में बदला में है। चीन के रॉकेट लांचर ने कंबोडिया से दगाबाजी कर दी।

चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से कंबोडिया थाईलैंड को निशाना बना रहा था। लेकिन कंबोडियाई सैनिक खुद ही शिकार बन गए। रॉकेट लांचर में धमाका हो गया और आठ कंबोडियाई सैनिक मारे गए। यानी कि थाईलैंड से तनाव में कंबोडिया को सस्ते चीनी हथियार भारी पड़ गए। ठीक वैसे ही जैसे चीन के हथियार ऑपरेशन सिंदूर में फेल हो गए थे। पाकिस्तान ने जिन चीनी मिसाइल ड्रोंस को लॉन्च किया था वो टारगेट से पहले से ही फुस हो गए थे। तब भी चीनी हथियारों की भदपिटी थी। अब सोशल मीडिया पर कंबोडिया की घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग चीनी सामानों की खिल्ली उड़ा रहे हैं।

दरअसल फिर से बढ़ गई जंग में कंबोडिया और थाईलैंड एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंबोडिया ने भी थाईलैंड को सबक सिखाने के लिए चीन से मंगाया एम270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूज़ करने का फैसला किया। यह भारत के पिनाका की तरह का रॉकेट सिस्टम है जिसके बारे में चीन का दावा है कि वह 1 मिनट में 44 रॉकेट फायर कर दुश्मन की धज्ज उड़ा सकता है। चीन के इसी भरोसे के बल पर कंबोडिया की सेना ने बॉर्डर पर इस सिस्टम को तैनात कर थाईलैंड पर फायर करना शुरू किया।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)